दैनिक
स्वर्णिम प्रदेश
PRN: MCN/329/2025-2027
epaper.swarnimpradesh.in
संरक्षक: मां वैष्णो देवी

विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें
अगर आप अपने विशेष अवसरों को खास बनाना चाहते हैं या महत्वपूर्ण सूचनाओं को व्यापक जनता तक पहुँचाना चाहते हैं, तो दैनिक स्वर्णिम प्रदेश आपके लिए सही मंच है। चाहे जन्मदिन की बधाई हो, शादी की सालगिरह, गुमशुदगी की सूचना, कानूनी नोटिस या कोई अन्य व्यक्तिगत और व्यावसायिक विज्ञापन, हम आपके संदेश को सही तरीके से पहुंचाने में मदद करेंगे। आपके विज्ञापन से समाचार पत्र को आर्थिक सहायता प्राप्त होगी, जो इसे और बेहतर सेवाएं प्रदान करने में मदद करेगी।
ईमेल: swarnimpradesh@yahoo.com
या वाट्सऐप नं. 8898271111

वर्ष : 8 • अंक : 359 • मुंबई, शनिवार 25 जुलाई, 2026 • पृष्ठ : 6 • मूल्य: 2 रुपये • संपादक : सुनील कुमार तिवारी • Email: swarnimpradesh@yahoo.com www.swarnimpradesh.in

पीएम मोदी के आश्वासन के बाद सोनम वांगचुक ने खत्म किया अनशन

संवाददाता

नई दिल्ली। नीट पेपर लीक मामले को लेकर 26 दिनों से जारी अनिश्चितकालीन अनशन को सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने समाप्त कर दिया। यह निर्णय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह के साथ हुई लंबी बातचीत के बाद लिया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक वीडियो संदेश जारी कर पेपर लीक के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और इस मुद्दे पर कैबिनेट स्तर पर बड़े फैसले का भरोसा दिया था। अनशन समाप्त होने के बाद सोनम वांगचुक ने कहा कि यह फैसला व्यापक बातचीत और देश में किसी भी प्रकार की हिंसा की आशंका को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। उन्होंने बताया कि विभिन्न राजनीतिक दलों के करीब 65 सांसदों ने भी उनसे मुलाकात कर या पत्र लिखकर अनशन समाप्त करने का अनुरोध किया था। वांगचुक ने कहा कि उनके इस निर्णय के पीछे कुछ महत्वपूर्ण शर्तें हैं, जिनकी जानकारी वह जल्द ही एक अलग वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे। साथ ही उन्होंने अपने समर्थकों से शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन जारी रखने और किसी भी तरह की हिंसा से दूर रहने की अपील की। इस दौरान जेपी नड्डा और डॉ. जितेंद्र सिंह की सफदरजंग अस्पताल में सोनम वांगचुक से मुलाकात का वीडियो भी सामने आया है। सूत्रों के अनुसार, सरकार और आंदोलनकारियों के बीच कई दौर की बातचीत के बाद कई अहम बिंदुओं पर सहमति बनी। प्रदर्शन में शामिल लोगों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने के सरकारी आश्वासन ने भी अनशन समाप्त कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सोनम वांगचुक ने 28 जून को उन छात्रों और युवाओं के समर्थन में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की थी, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। उनकी प्रमुख मांगों में परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करना, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और भविष्य में पेपर लीक रोकने के लिए प्रभावी व्यवस्था लागू करना शामिल था। लगातार उपवास के कारण 18 जुलाई को उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। डॉक्टरों की सलाह और अदालत के निर्देश पर दिल्ली पुलिस उन्हें सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराकर इलाज के लिए ले गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो संदेश और सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर किए गए पोस्ट में कहा कि पेपर लीक के खिलाफ और सख्त कदम कल की कैबिनेट बैठक में उठाए जाएंगे। प्रधानमंत्री के इस आश्वासन के बाद आंदोलन के समाधान की दिशा में सकारात्मक माहौल बना और देर रात सोनम वांगचुक ने अपना अनशन समाप्त करने की घोषणा कर दी।

चर्चा, मुआवजा और शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर नहीं होगी कार्रवाई, सरकार ने दिया आश्वासन : वांगचुक

इस संबंध में उन्होंने एक वीडियो जारी कर कहा है कि देश में जवाब देही तय होनी चाहिए। उन्होंने सरकार के साथ हुई बातचीत और आश्वासन की भी जानकारी दी है। हालांकि, इसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे बात नहीं है। सोनम वांगचुक का कहना है कि सरकार ने और अन्य पार्टियों के नेताओं ने उन्हें आश्वासन दिया है कि संसद में परीक्षा तंत्र की विफलता की जवाबदेही तय करने के लिए चर्चा होगी। साथ ही सरकार नीट परीक्षा पत्र लिक से जुड़े आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिजनों को सरकार उचित मुआवजा देगी। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार ने उन्हें आश्वासन दिया है कि शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करने वाले छात्रों और युवाओं के खिलाफ कोई कैसे कोई मामला दर्ज नहीं होगा। इसी बीच ऐसी जानकारी मिली है कि सरकार जंतर मंतर पर आंदोलनरत सीजेपी नेताओं से कांस्टीट्यूशनल क्लब में बातचीत कर सकती है। सरकार और भाजपा की ओर से इस संबंध में अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। वहीं, सीजेपी का नेतृत्व कर रहे अभिजीत दीपके ने कहा है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि वह सोनम वांगचुक के त्याग को ऐसे ही व्यर्थ नहीं जाने देंगे।

मप्र में फिर गरमाया भोजशाला विवाद

चालीसपीर दरगाह पर नहीं हुई जुमे की नमाज

- मुस्लिम पक्ष भोजशाला के पास वाली जगह के लिए अड़ा, शहर में 350 सुरक्षाकर्मी तैनात

संवाददाता

धार। मध्य प्रदेश के धार जिला मुख्यालय स्थित ऐतिहासिक भोजशाला-कमाल मौला मस्जिद परिसर को लेकर चल रहा विवाद एक बार फिर गरमा गया है। यहां शुक्रवार को प्रशासन द्वारा निर्धारित मालीवाड़ा में चालीसपीर दरगाह के पास जुमे की नमाज अदा नहीं की गई। मुस्लिम पक्ष नमाज के लिए भोजशाला के पास वाली जगह देने की मांग पर उड़ा हुआ है।

उच्चतम न्यायालय ने बीती 14 जुलाई को मुस्लिम पक्ष को जुमे की नमाज के लिए भोजशाला के पास जगह उपलब्ध कराने के निर्देश जिला प्रशासन को दिए थे। न्यायालय ने कहा था कि हर शुक्रवार दोपहर 1 से 3 बजे के बीच नमाज के लिए वैकल्पिक स्थान मुहैया कराया जाए। इसके बाद जिला प्रशासन ने मालीवाड़ा गांव में चालीसपीर दरगाह के पास नमाज की जगह निर्धारित की थी लेकिन मुस्लिम समुदाय ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। इसी को लेकर गुरुवार देर रात जिला प्रशासन और मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधियों के बीच करीब दो घंटे तक चली बैठक में अन्य संभावित स्थानों का प्रस्ताव रखा गया लेकिन नमाज के वैकल्पिक स्थान को लेकर सहमति नहीं बन पाई। इसके चलते शुक्रवार को प्रशासन द्वारा निर्धारित मालीवाड़ा में चालीसपीर दरगाह के पास जुमे की नमाज अदा करने के लिए कोई नहीं पहुंचा। सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन और पुलिस की ओर से मौके पर सभी इंतजाम किए गए थे। मुस्लिम समाज का कहना है कि उन्हें उनके पारंपरिक स्थान पर ही नमाज अदा करने की अनुमति दी जाए। धार के सदर अब्दुल समद ने कहा कि प्रशासन उच्च न्यायालय के आदेश का पालन नहीं कर रहा है। जब भोजशाला परिसर में नमाज होती थी, तब भी कभी कानून-व्यवस्था की स्थिति नहीं बिगड़ी। नमाज बंद होने के बाद भी कोई विवाद नहीं हुआ इसलिए इतनी दूर वैकल्पिक व्यवस्था का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने कहा कि चालीसपीर दरगाह के पास निर्धारित स्थान पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। इसके बजाय जुमे की नमाज आसपास की मस्जिदों में अदा की जाएगी। सदर ने पुरानी घटना का जिक्र करते हुए बताया कि इससे पहले 23 जनवरी को बसंत पंचमी के मौके पर प्रशासन ने जिस जगह पर डमी नमाज कराई थी, वह दरअसल कब्रिस्तान की जमीन है। उस समय भी मुस्लिम समाज ने इस पर आपत्ति जताई थी क्योंकि कब्रिस्तान में जुमे की नमाज अदा नहीं की जाती। यह पक्ष भी उच्चतम न्यायालय के सामने मजबूती से रखा गया था। वहीं, हिन्दू पक्ष की ओर से भोजशाला मुक्ति यज्ञ समिति के संयोजक गोपाल शर्मा ने कहा कि प्रशासन ने मालीवाड़ा में नमाज के लिए उपयुक्त स्थान उपलब्ध कराया है लेकिन अंतरिम आदेश की आड़ में मस्जिद पक्ष जिस स्थान पर नमाज की मांग कर रहा है, वह न तो न्यायोचित है और न ही शहर की शांति व्यवस्था के लिहाज से उचित है। इधर, जुमे की नमाज को लेकर शुक्रवार सुबह से ही शहर में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। जावरा और इंदौर से पुलिस की दो विशेष कंपनियां बुलाई गई हैं। पूरे नगर में सुरक्षा व्यवस्था के लिए 350 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं।

खास खबर

सीजेपी ने देशव्यापी छात्र आंदोलन को जारी रखने का लिया निर्णय

नई दिल्ली। सोशल मीडिया अभियान कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने शुक्रवार को देशव्यापी छात्र आंदोलन को जारी रखने का निर्णय लिया। अभियान प्रमुख अभिजीत दिपके ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर शुक्रवार को आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, देश के युवाओं की बहुत सरल और स्पष्ट एक ही मांग है। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक शिक्षा मंत्री पद नहीं छोड़ देते। अगर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) या सरकार इस मुद्दे को सुलझाना चाहती है, तो सिर्फ़ एक ही समाधान है। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही होगा। उन्होंने यह भी कहा कि हमें बहुत खुशी और राहत है कि पर्यावरणविद् सोनम वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी है। वे 26 दिनों से उपवास पर थे और उन्होंने छात्रों की भलाई के लिए हड़ताल खत्म करने का फैसला किया। वे नहीं चाहते थे कि किसी भी छात्र के खिलाफ कोई मामला दर्ज हो और यही उनकी शर्त थी। हम सचमुच उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। अपनी जान जोखिम में डालकर उन्होंने पूरे देश के लोगों को जगाया। सोनम ने इस देश और इसकी आने वाली पीढ़ियों के लिए जो किया है, उसे इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। पूरे देश में जागरूकता फैलाने के लिए यह कदम उठाने पर हम उनका धन्यवाद करते हैं। इससे बहुत बड़ा बदलाव आया है और उनकी कोशिशों की वजह से पूरे भारत में इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ है।

मणिपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, तीन उग्रवादी कैडर-एक ड्रग तस्कर गिरफ्तार

इंफाल। मणिपुर पुलिस ने 23 जुलाई को राज्यभर में चलाए गए अलग-अलग अभियानों के दौरान प्रतिबंधित उग्रवादी संगठनों से जुड़े तीन सक्रिय कैडरों और एक संदिग्ध ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया। कार्रवाई के दौरान हथियार, गोलियां और भारी मात्रा में संदिग्ध हेरोइन भी बरामद की गई। शुक्रवार को दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार, बिष्णुपुर थाना क्षेत्र के तेरा उराक चेकपोस्ट से पुलिस ने केवाईकेएल के कथित सक्रिय कैडर और रंगदारी वसूली में संलिप्त मयांगलाम्बम टोम्बा सिंह उर्फ लक्ष्पा (39) को गिरफ्तार किया। वह मूल रूप से चुराचांदपुर के बिजांग खुनौ का निवासी है और वर्तमान में फुबाला राहत शिविर में रह रहा था। पुलिस के अनुसार, वह मोइरांग स्थित एक पेट्रोल पंप में हुए विस्फोट की घटना में भी कथित रूप से शामिल था। उसके कब्जे से एक 9 एमएम पिस्तौल, एक मैगजीन तथा विभिन्न बोर के 11 जिंदा कारतूस बरामद किए गए।

नेपाल सीमा से घुसपैठ का बड़ा नेटवर्क बेनकाब : अमेरिका से आया 'वारिस पंजाब दे' का सक्रिय सदस्य समेत पांच गिरफ्तार

- फर्जी दस्तावेजों के सहारे भारत में घुसपैठ की साजिश
- एसएसबी और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में खुलासा

संवाददाता

बहराइच। भारत-नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर अवैध घुसपैठ कराने वाले एक संगठित नेटवर्क का बहराइच पुलिस और एसएसबी ने शुक्रवार को पर्दाफाश किया है। संयुक्त कार्रवाई में अमेरिका से आए प्रतिबंधित संगठन 'वारिस पंजाब दे' के सक्रिय सदस्य समेत पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस अधीक्षक विश्वजीत श्रीवास्तव ने बताया कि रुपईडीहा थाना क्षेत्र के बीआईटी चेक पोस्ट पर विशेष खुफिया सूचना के आधार पर एसएसबी और पुलिस की संयुक्त टीम ने गुरुवार की रात को नेपाल से भारत में अवैध प्रवेश कर रहे संदिग्धों को रोका। पूछताछ और जांच में खुलासा हुआ कि गिरफ्तार लोगों में अमेरिका के कैलिफोर्निया निवासी मनवीर सिंह ढिल्लों तथा पंजाब निवासी विक्रमजीत सिंह शामिल हैं, जो 'वारिस पंजाब दे' संगठन से जुड़े बताए जा रहे हैं। इनके साथ तीन स्थानीय सहयोगियों राहुल कुमार, सुरेश कुमार पाठक और दिलीप पाठक उर्फ राहुल पाठक को भी गिरफ्तार किया गया। जांच में सामने आया कि आरोपित फर्जी पहचान पत्र तैयार कर और स्थानीय सहयोगियों की मदद से नेपाल के रास्ते भारत में अवैध घुसपैठ कर रहे थे। पूछताछ में आरोपितों के पास संगठन और गतिविधियों से जुड़े कई महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं। पंजाब पुलिस से भी संपर्क कर उनके आपराधिक इतिहास और नेटवर्क की जानकारी जुटाई जा रही है। फर्जी दस्तावेज और विदेशी सामान बरामद गिरफ्तार आरोपियों से अमेरिकी पासपोर्ट, आईफोन, बैंक ऑफ अमेरिका का डेबिट कार्ड, विदेशी क्रेडिट कार्ड, फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, भारतीय और नेपाली मुद्रा के अलावा एक कार और मोटरसाइकिल बरामद हुई है। बरामद दस्तावेजों की सत्यता की जांच कराई जा रही है। पहले से दर्ज हैं गंभीर मुकदमे पुलिस के अनुसार, विक्रमजीत सिंह और मनवीर सिंह ढिल्लों के खिलाफ पंजाब में पहले से गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। बहराइच में भी दोनों समेत अन्य आरोपितों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), फर्जी दस्तावेज तैयार करने, धोखाधड़ी तथा विदेशी नागरिकों से जुड़े प्रावधानों के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।

खोपोली के ऐतिहासिक वीरेश्वर मंदिर से 17 किलो चांदी की परत चोरी मामले में चार आरोपी गिरफ्तार

संवाददाता

नवी मुंबई। रायगढ़ जिले के खोपोली स्थित ऐतिहासिक पेशवा-कालीन वीरेश्वर मंदिर में शिवलिंग पर चढ़ी लगभग 17 किलोग्राम चांदी की परत चोरी करने के आरोप में खोपोली पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की गई चांदी की परत भी बरामद कर ली है। पुलिस के अनुसार, चोरी की घटना 19 जुलाई की तड़के करीब 2:30 बजे हुई, जब आरोपी कथित रूप से मंदिर परिसर में घुसे और शिवलिंग पर लगी चांदी की परत चोरी कर फरार हो गए। घटना के बाद क्षेत्र के श्रद्धालुओं और स्थानीय नागरिकों में आक्रोश फैल गया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अमोल सुरेश कसबे (36) और विलास साहेबराव अगिवाले (25), निवासी शिरूर (जिला पुणे), तथा दिलीप राजू जाधव (40) और सखाराम छबन गायकवाड़ (40), निवासी पारनेर (जिला अहिल्यानगर) के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि चोरी की पूरी वारदात मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई थी।

शेष पेज 2 पर...

शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर युवाओं का भविष्य छीना, छात्रों पर दमन से सरकार ने लोकतंत्र को शर्मसार किया : सोनिया गांधी

संवाददाता

नई दिल्ली। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर देश की शिक्षा व्यवस्था को व्यवस्थित रूप से कमजोर करने, सार्वजनिक शिक्षा को पीछे धकेलने, परीक्षा प्रणाली को भ्रष्टाचार और अव्यवस्था का शिकार बनाने तथा छात्रों के शांतिपूर्ण आंदोलन को बलपूर्वक कुचलने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 152 प्रश्नपत्र लीक, शिक्षा के बढ़ते निजीकरण, युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी और जवाबदेही से सरकार के लगातार बचने ने देश के छात्रों को सड़क पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया है। छात्रों की जायज मांगों का जवाब संवाद से नहीं, बल्कि लाठीचार्ज, आंसू गैस और दमन से दिया गया, जो लोकतंत्र के

लिए गंभीर चिंता का विषय है। सोनिया गांधी ने शुक्रवार को एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित अपने लेख 'शिक्षा व्यवस्था का पतन और युवा भारत की त्रासदी' में कहा कि पिछले कुछ सप्ताह से देशभर के छात्र प्रश्नपत्र लीक और शिक्षा व्यवस्था के पतन के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांगें केवल जवाबदेही तय करने और शिक्षा सुधार लागू करने की हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने उनकी आवाज सुनने के बजाय उनके साथ क्रूर व्यवहार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि 20 जुलाई को दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों ने छात्रों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन को बलपूर्वक दबाने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। इस कार्रवाई में बड़ी संख्या में छात्र घायल हुए। घर लौट रहे छात्रों तक को नहीं बख्शा गया और उनके सिर व पीठ पर लाठियां बरसाई गईं। उन्होंने आरोप लगाया कि पेलेट के इस्तेमाल की अनुमति भी केंद्रीय गृह मंत्री के स्तर पर दी गई होगी। उस दिन के दृश्य पूरे देश की सामूहिक चेतना को झकझोरने वाले थे। सोनिया गांधी ने कहा कि मोदी सरकार संवाद की बजाय हिंसा को प्राथमिकता देती है। किसानों के आंदोलन से लेकर सामाजिक कार्यकर्ताओं तक और अब छात्रों के साथ भी यही रवैया अपनाया गया है। भविष्य के डॉक्टरों, इंजीनियरों, शिक्षकों, प्रशासनिक अधिकारियों और उद्यमियों के साथ संवाद स्थापित करने के बजाय सरकार ने उनके खिलाफ राज्य की दमनकारी ताकत का इस्तेमाल किया, जिसे न भुलाया जा सकता है और न ही माफ किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार ने हर विरोध को राष्ट्रविरोधी बताने की पुरानी रणनीति को छात्र आंदोलन पर भी लागू करने का प्रयास किया। छात्रों की वास्तविक समस्याओं पर आत्ममंथन करने के बजाय सरकार ने उन पर साजिश और राजनीतिक प्रेरणा के आरोप लगाने शुरू कर दिए। लेख में सोनिया गांधी ने सार्वजनिक शिक्षा के कमजोर होने को संकट की पहली बड़ी वजह बताया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने स्कूल शिक्षा पर कुल बजट व्यय का हिस्सा 50 प्रतिशत तथा उच्च शिक्षा पर 23 प्रतिशत तक घटा दिया। पिछले 12 वर्षों में लगभग एक लाख सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए, जबकि 43 हजार निजी स्कूल खोले गए, जिनमें बड़ी संख्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उससे जुड़े संगठनों द्वारा संचालित हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों की अनुदान राशि घटाकर उन्हें कर्ज लेने के लिए मजबूर किया, जिसके कारण सार्वजनिक विश्वविद्यालयों को फीस बढ़ानी पड़ी। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण और सस्ती सार्वजनिक शिक्षा की उपलब्धता घटने के कारण परिवारों पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है।

संपादकीय

संवाद की जीत या दबाव की राजनीति?

सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने 26 दिनों तक चले अपने अनशन को समाप्त कर दिया है। यह फैसला ऐसे समय आया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा प्रणाली में सुधार, पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून और जवाबदेही सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया। साथ ही केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों के साथ कई दौर की बातचीत के बाद कुछ लिखित आश्वासन भी दिए गए। इसके बाद वांगचुक ने अनशन समाप्त करते हुए देश में शांति बनाए रखने और हिंसा से बचने की अपील की। लोकतंत्र में विरोध और संवाद दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। जब कोई व्यक्ति अपने विचारों को शांतिपूर्ण तरीके से रखने के लिए अनशन का सहारा लेता है, तो वह केवल सरकार से नहीं बल्कि पूरे समाज से जवाब मांग रहा होता है। दूसरी ओर, किसी भी लोकतांत्रिक सरकार का दायित्व है कि वह विरोध की आवाज़ को सुने और समय रहते समाधान खोजे। इस पूरे घटनाक्रम ने यही प्रश्न फिर सामने रखा है कि क्या हमारे लोकतांत्रिक संस्थान जनता की चिंताओं का समाधान संवाद के माध्यम से समय पर कर पा रहे हैं? सोनम वांगचुक का यह अनशन केवल एक व्यक्ति का आंदोलन नहीं था। यह उन लाखों छात्रों की चिंता का प्रतीक बन गया, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता की मांग कर रहे हैं। लगातार सामने आए पेपर लीक और परीक्षा संबंधी विवादों ने युवाओं के विश्वास को गहरा आघात पहुंचाया है। वर्षों की मेहनत करने वाले विद्यार्थियों के लिए ऐसी घटनाएं केवल परीक्षा नहीं, बल्कि उनके भविष्य पर सीधा प्रहार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार सार्वजनिक रूप से इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून, त्वरित न्यायिक प्रक्रिया और शिक्षा व्यवस्था में सुधार का भरोसा दिलाया। इसके साथ ही उन्होंने वांगचुक से स्वास्थ्य का ध्यान रखने और अनशन समाप्त करने की अपील भी की। सरकार का यह कदम सकारात्मक माना जा सकता है, क्योंकि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में संवाद टकराव से बेहतर विकल्प होता है। हालांकि, केवल आश्वासन देना पर्याप्त नहीं होगा। देश ने पहले भी कई ऐसे अवसर देखे हैं, जब बड़े वादे किए गए, लेकिन उनका क्रियान्वयन अपेक्षित गति से नहीं हुआ। छात्रों का विश्वास तभी लौटेगा जब दोषियों के खिलाफ निष्पक्ष कार्रवाई होगी, परीक्षा प्रणाली में तकनीकी सुधार किए जाएंगे और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी व्यवस्था बनाई जाएगी। इस पूरे घटनाक्रम का एक दूसरा पक्ष भी है। सरकार और आंदोलनकारियों के बीच अंततः बातचीत हुई और कुछ महत्वपूर्ण सहमतियां बनीं। बताया गया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई नहीं होगी, संसद में परीक्षा सुधारों पर चर्चा होगी और प्रभावित परिवारों के मुद्दों पर भी विचार किया जाएगा। यदि इन वादों को समयबद्ध तरीके से लागू किया जाता है, तो यह लोकतांत्रिक संवाद की एक सकारात्मक मिसाल बन सकती है। साथ ही यह भी याद रखना होगा कि किसी भी आंदोलन का उद्देश्य समाधान होना चाहिए, टकराव नहीं। वांगचुक ने स्वयं अनशन समाप्त करते समय हिंसा से दूर रहने और शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक तरीकों पर भरोसा रखने की अपील की। यह संदेश अत्यंत महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र में असहमति का अधिकार है, लेकिन उसका स्वरूप शांतिपूर्ण और संवैधानिक होना चाहिए। सरकार के लिए भी यह अवसर आत्ममंथन का है। युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी, प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता और प्रशासनिक जवाबदेही जैसे मुद्दे केवल राजनीतिक बहस का विषय नहीं हैं। ये देश के भविष्य से जुड़े प्रश्न हैं। यदि योग्य छात्रों का भरोसा व्यवस्था से उठने लगे, तो इसका प्रभाव केवल शिक्षा तक सीमित नहीं रहता बल्कि पूरे सामाजिक और आर्थिक ढांचे पर पड़ता है। यह भी स्पष्ट है कि भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में केवल कानून बनाना पर्याप्त नहीं है। कानून के साथ पारदर्शी व्यवस्था, आधुनिक तकनीक, मजबूत निगरानी और जवाबदेह प्रशासन भी आवश्यक है। पेपर लीक रोकने के लिए परीक्षा एजेंसियों की कार्यप्रणाली में व्यापक सुधार और डिजिटल सुरक्षा को प्राथमिकता देनी होगी। अंततः, सोनम वांगचुक का अनशन समाप्त होना किसी पक्ष की हार या जीत नहीं माना जाना चाहिए। यदि सरकार अपने वादों को समयबद्ध तरीके से लागू करती है और आंदोलनकारी लोकतांत्रिक संवाद पर भरोसा बनाए रखते हैं, तो इसे लोकतंत्र की सफलता कहा जा सकता है। लेकिन यदि आश्वासन केवल कागज़ों तक सीमित रह गए, तो युवाओं का भरोसा फिर टूटेगा और असंतोष और गहरा होगा। आज आवश्यकता इस बात की है कि सरकार और समाज दोनों यह समझें कि देश की सबसे बड़ी पूंजी उसका युवा वर्ग है। उनकी मेहनत, उम्मीदों और भविष्य की रक्षा करना केवल राजनीतिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि राष्ट्रीय दायित्व है। यही इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा संदेश भी है।

छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा: सिंधिया

संवाददाता

ग्वालियर। केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पेपर लीक के विरोध में चल रहे छात्र आंदोलन पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। केन्द्रीय मंत्री सिंधिया ने शुक्रवार को ग्वालियर में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि विद्यार्थी देश का भविष्य हैं और उनकी मेहनत के साथ किसी भी तरह का अन्याय स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जैसे ही अनियमितताओं की जानकारी सामने आई, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के निर्देश पर तत्काल कार्रवाई शुरू की गई। सरकार इस पूरे मामले में दोषियों के खिलाफ कठोर कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि समाज, क्षेत्र और देश का नाम रोशन करने के लिए मेहनत करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का संदेश

स्पष्ट है कि विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खेलने वालों पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। सिंधिया ने बताया कि इस मामले में कैबिनेट में एक विधेयक लाया जा रहा है, जिसके तहत फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा। इससे पेपर लीक जैसे मामलों की शीघ्र सुनवाई होगी और दोषियों को जल्द सजा दिलाई जा सकेगी। उन्होंने कहा कि छात्रों के हितों की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है और परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए हर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। केन्द्रीय मंत्री सिंधिया शुक्रवार को मध्य प्रदेश के चुनावी दौरे पर हैं। वे दतिया विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के समर्थन में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। दतिया रवाना होने से पहले उन्होंने ग्वालियर में मीडिया से बातचीत करते हुए दतिया विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत का भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि यह चुनाव विकास का चुनाव है और केंद्र व प्रदेश की डबल इंजन सरकार दतिया के सर्वांगीण विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे। सिंधिया ने दतिया पहुंचकर पीतांबरा पीठ में पूजन और वनखंडेश्वर महादेव में किया जलाभिषेक इसके बाद केंद्रीय मंत्री सिंधिया ग्वालियर से सड़क मार्ग के जरिए दतिया पहुंचे।

पेज 1 का शेष...

खोपोली के ऐतिहासिक...

हालांकि, मंदिर के बाहर लगे कई सीसीटीवी कैमरे बंद होने के कारण आरोपियों के भागने के मार्ग का पता लगाने में शुरुआती कठिनाई आई। घटना की गंभीरता को देखते हुए रायगढ़ की पुलिस अधीक्षक अंचल दलाल ने स्वयं घटनास्थल का निरीक्षण किया और जांच के निर्देश दिए। उनके मार्गदर्शन में उपविभागीय पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ) डॉ. विशाल नेहुल पाटिल तथा खोपोली पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सचिन हिरे की निगरानी में जांच शुरू की गई। मामले के खुलासे के लिए आठ विशेष जांच टीमों का गठन किया गया। जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज, फास्टैग डेटा, तकनीकी विश्लेषण और खुफिया सूचनाओं के आधार पर पुलिस को पता चला कि घटना के बाद संदिग्धों का वाहन कर्जत की ओर गया था। इसके बाद पुलिस ने पुणे के शिरूर और अहिल्यानगर के पारनेर में छापेमारी कर चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की गई 17 किलोग्राम चांदी की परत सहित अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की है। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि इस वारदात में कोई अन्य व्यक्ति या गिरोह भी शामिल था या नहीं।

केंद्र ने कर्नाटक-आंध्र प्रदेश में रेलवे मल्टीट्रैकिंग परियोजना को दी मंजूरी

संवाददाता

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने शुक्रवार को कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी–गुंटाकल सेक्शन पर तीसरी और चौथी लाइन बिछाने की परियोजना को मंजूरी दी। इस परियोजना की अनुमानित लागत 1,264 करोड़ रुपये है और इसे वर्ष 2028-29 तक पूरा किया जाएगा। सूचना एवं प्रसारण और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यहां राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि यह परियोजना पीएम-गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत तैयार की गई है, जिसका उद्देश्य मल्टी-मॉडल

कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक दक्षता को बढ़ाना है। परियोजना से भारतीय रेल नेटवर्क में लगभग 46 किलोमीटर की वृद्धि होगी और तीन जिलों के करीब 99 गांवों को बेहतर रेल संपर्क मिलेगा। इन गांवों की आबादी लगभग सात लाख है। इस परियोजना से लौह अयस्क, डोलोमाइट, चूना पत्थर, इस्पात, कोयला, खाद और खाद्यान्न जैसी वस्तुओं के परिवहन की क्षमता बढ़ेगी। अनुमान है कि अतिरिक्त माल यातायात 16.22 मिलियन टन प्रति वर्ष तक बढ़ेगा। परियोजना से तेल आयात में 1.32 करोड़ लीटर की बचत होगी और कार्बन उत्सर्जन में 6.67 करोड़ किलो की कमी आएगी, जो 0.27 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है। परियोजना से बल्लारी किला और श्री कुमार स्वामी मंदिर जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों तक रेल संपर्क भी बेहतर होगा। इससे परिचालन दक्षता और सेवा विश्वसनीयता में सुधार होगा तथा क्षेत्रीय विकास को गति मिलेगी।

एल.आई.सी

भारतीय जीवन बीमा से संबंधित किसी भी जानकारी या समस्या समाधान हेतु संपर्क करें।

-भारत सिंह

मो. 9967255741

महत्वपूर्ण सूचना

विज्ञापन प्रति के स्वीकृति पूर्व एहतियातन बरती जाने के बावजूद, उसमें अंतर्भूत बाते जाँचना संभव नहीं है। ऐसी अंतर्भूत बातों के लिए दैनिक स्वर्णिम प्रदेश के अंतर्गत समाचार पत्र या प्रकाशनों में आनेवाली कंपनियां, संस्थाए या व्यक्तिगत विज्ञापनों के साथ हुए किसी भी प्रकार के व्यवहार के लिए समाचार पत्र जिम्मेदार नहीं है।

छत्तीसगढ़ में 7,854 करोड़ की नई दोहरी रेल लाइन परियोजना को मिलेगी रफ्तार

संवाददाता

नई दिल्ली/रायपुर। छत्तीसगढ़ में रेल संपर्क और माल परिवहन को मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार ने खरसिया-नया रायपुर-परमलकसा नई दोहरी रेल लाइन परियोजना को मंजूरी दी है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज शुक्रवार को राज्यसभा में लिखित उत्तर में बताया कि अप्रैल 2025 में 278 किलोमीटर लंबी इस परियोजना को 7,854 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से स्वीकृति दी गई थी। यह रेल लाइन बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग जैसे व्यस्त रेल सेक्शनों को बाईपास करेगी, जिससे मालगाड़ियों और यात्री ट्रेनों की आवाजाही तेज और सुगम होगी। परियोजना छत्तीसगढ़ के आठ जिलों से होकर गुजरेगी और विशेष रूप से बलौदाबाजार जिले को पहली बार रेल नेटवर्क से जोड़ेगी। साथ ही खरसिया, जो महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) के कोयला क्षेत्रों का प्रमुख रेल प्रवेश द्वार है,

वहां से माल परिवहन को भी नई गति मिलेगी। परियोजना को 'विशेष रेलवे परियोजना' घोषित किया गया है। इसके लिए लगभग 1,852 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होगी और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज़ी से जारी है। रेल मंत्रालय के अनुसार, वर्ष 2026-27 में छत्तीसगढ़ के लिए रेलवे का बजट बढ़कर लगभग 7,470 करोड़ रुपये हो गया है, जो 2009-14 के औसत वार्षिक आवंटन से लगभग 24 गुना अधिक है। वर्ष 2014 से 2026 के बीच राज्य में 1,311 किलोमीटर नई रेल पटरियां चालू की गई हैं। वर्तमान में राज्य में 48,202 करोड़ रुपये की लागत वाली 36 रेल परियोजनाओं पर कार्य जारी है। इनमें 8 नई रेल लाइन और 28 दोहरीकरण परियोजनाएं शामिल हैं। मंत्रालय ने बताया कि, परियोजनाओं के पूरा होने की समय-सीमा भूमि अधिग्रहण, वन स्वीकृतियों और अन्य तकनीकी एवं प्रशासनिक प्रक्रियाओं पर निर्भर करेगी।

हर पंचायत में होगी खेल प्रतिभाओं की खोज, मिलेगा विश्वस्तरीय मंच: सम्राट चौधरी

संवाददाता

पटना। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार प्रत्येक पंचायत में विशेष अभियान चलाकर खेल प्रतिभाओं की पहचान करेगी और उन्हें विश्वस्तरीय प्रशिक्षण एवं मंच उपलब्ध कराएगी। उन्होंने कहा कि खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मान और रोजगार उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है तथा बिहार को राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में लगातार कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री शुक्रवार को पटना स्थित ऊर्जा ऑडिटोरियम में खेल विभाग की ओर से आयोजित 'मेडल लाओ, नौकरी पाओ' योजना के तहत नियुक्ति-पत्र एवं खेल छात्रवृत्ति चयन-पत्र वितरण समारोह का उद्घाटन करने के बाद संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में खिलाड़ियों के लिए सुनहरे भविष्य का एक नया अध्याय शुरू हुआ है। राज्य सरकार ने खिलाड़ियों को सरकारी सेवा में नियुक्ति देकर यह स्पष्ट संदेश दिया है कि उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली प्रतिभाओं को हर स्तर पर सम्मान और प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह बिहार के लिए गर्व की बात है कि पहली बार

किसी खिलाड़ी को पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) जैसे उच्च पद पर नियुक्ति दी गई है। इससे राज्य के खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ेगा और युवा खेलों में बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित होंगे। सम्राट चौधरी ने कहा कि सरकार खिलाड़ियों के प्रशिक्षण, आधुनिक खेल सुविधाओं और खेल अवसंरचना के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने बताया कि आगामी 15 सितंबर से पंचायत स्तर पर खेल प्रतिभा खोज अभियान शुरू किया जाएगा। चयनित खिलाड़ियों को व्यवस्थित प्रशिक्षण देकर उनकी प्रतिभा को निखारा जाएगा, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के खिलाड़ी भी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले दो वर्षों में राज्य सरकार ने बिहार के विभिन्न हिस्सों में 5,000 खेल मैदानों का निर्माण पूरा किया है। इसका उद्देश्य गांव-गांव तक खेल संस्कृति को बढ़ावा देना और युवाओं को बेहतर खेल सुविधाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि बिहार में विश्वस्तरीय खेल अवसंरचना विकसित करने के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है। पटना स्थित मोइनुल हक स्टेडियम का पुनर्विकास कराया जा रहा है, जबकि इसके संचालन की जिम्मेदारी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) को सौंपी गई है। लगभग 40 हजार दर्शकों की क्षमता वाला यह स्टेडियम आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा और भविष्य में राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की मेजबानी करने में सक्षम होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने खेलों को नई पहचान देने के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। नालंदा में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है। साथ ही राज्य में तीन अलग-अलग खेलों के विश्व कप स्तर के आयोजनों का सफल संचालन हुआ, जिनमें भारतीय टीम ने खिताब अपने नाम किए। उन्होंने कहा कि इन उपलब्धियों से बिहार को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल जगत में नई पहचान मिली है। हमारा लक्ष्य राष्ट्रीय खेलों में बिहार को शीर्ष स्थान पर पहुंचाना है। समारोह के दौरान अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी मुकेश कुमार और आकाश दीप को पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी), जबकि एथलेटिक्स खिलाड़ी पियूष राज को पुलिस अवर निरीक्षक (एसआई) के पद पर नियुक्ति-पत्र प्रदान किया गया। इसके अलावा पांच पैरा खिलाड़ियों सहित विभिन्न खेल विधाओं के कई उत्कृष्ट खिलाड़ियों को भी सरकारी सेवा के नियुक्ति-पत्र सौंपे गए।

मेष: कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय सोच-समझकर करें। व्यवसाय ठीक चलेगा। धार्मिक अनुष्ठान पूजा-पाठ इत्यादि का कार्यक्रम आयोजित हो सकता है। कोर्ट-कचहरी के कार्य मनोनुकूल रहेंगे। मानसिक शांति रहेगी। लाभ के अवसर हाथ आएंगे। समय अनुकूल है।

वृषभ: बकाया वसूली के प्रयास सफल रहेंगे। व्यावसायिक यात्रा लाभदायक रहेगी। भाग्य का साथ मिलेगा। नौकरी में चैन रहेगा। निवेश शुभ रहेगा। घर-बाहर प्रसन्नता रहेगी। पार्टनरों का सहयोग मिलेगा। प्रमाद न करें। कीमती वस्तुएं संभालकर रखें। शारीरिक कष्ट संभव है।

मिथुन: कार्यप्रणाली में सुधार होगा। सामाजिक काम करने की इच्छा रहेगी। मान-सम्मान मिलेगा। सुख के साधन प्राप्त होंगे। नई योजना बनेगी। तत्काल लाभ नहीं मिलेगा। व्यापार-व्यवसाय लाभदायक रहेगा। नौकरी में मातहतों का सहयोग मिलेगा। घर-बाहर प्रसन्नता रहेगी।

कर्क: व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी। कारोबार में वृद्धि के योग हैं। शारीरिक कष्ट संभव है। किसी व्यक्ति से कहासुनी हो सकती है। स्वाभिमान को ठेस लग सकती है। जोखिम व जमानत के कार्य टालें। आय बनी रहेगी। पुराना रोग उभर सकता है। अप्रत्याशित खर्च सामने आएंगे। कर्ज लेना पड़ सकता है।

सिंह: किसी दूसरे व्यक्ति की बातों में न आएं। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय सोच-समझकर करें। व्यापार अच्छा चलेगा। नौकरी में मातहतों से कहासुनी हो सकती है। लेन-देन में सावधानी रखें। कुसंगति से बचें। वाहन व मशीनरी के प्रयोग में सावधानी रखें। पुराना रोग उभर सकता है।

कन्या: घर-बाहर प्रसन्नता रहेगी। भाइयों का सहयोग मिलेगा। परिवार में मांगलिक कार्य हो सकता है। धन प्राप्ति सुगम होगी। शरीर में कमर व घुटने आदि के दर्द से परेशानी हो सकती है। लेन-देन में सावधानी रखें। चिंता तथा तनाव रहेंगे। शत्रुभय रहेगा। कोर्ट व कचहरी के कार्य अनुकूल रहेंगे।

तुला: धनलाभ के अवसर हाथ आएंगे। भूमि व भवन संबंधी बाधा दूर होगी। बड़ा लाभ हो सकता है। रोजगार प्राप्ति के प्रयास सफल रहेंगे। परीक्षा व साक्षात्कार आदि में सफलता मिलेगी। भाग्य का साथ रहेगा। शेयर मार्केट से लाभ होगा। शत्रु पस्त होंगे। सुख के साधनों की प्राप्ति पर व्यय होगा।

वृश्चिक: किसी वरिष्ठ प्रबुद्ध व्यक्ति का मार्गदर्शन व सहयोग प्राप्त होगा। व्यापार से लाभ होगा। नौकरी में प्रभाव बढ़ेगा। प्रेम-प्रसंग में अनुकूलता रहेगी। कष्ट व भय सताएंगे। भाग्य का साथ मिलेगा। किसी मांगलिक कार्य में भाग लेने का अवसर प्राप्त होगा। विद्यार्थी वर्ग सफलता प्राप्त करेगा।

धनु: कीमती वस्तुएं संभालकर रखें। दुःखद समाचार प्राप्त हो सकता है। भागदौड़ अधिक रहेगी। थकान व कमजोरी महसूस होगी। आय में निश्चितता रहेगी। व्यापार ठीक चलेगा। निवेश सोच-समझकर करें। राजभय रहेगा। वाणी पर नियंत्रण रखें। शारीरिक कष्ट संभव है। यात्रा में जल्दबाजी न करें।

मकर: प्रयास सफल रहेंगे। सामाजिक कार्यों में रुचि रहेगी। मान-सम्मान मिलेगा। नौकरी में प्रशंसा होगी। कार्यसिद्धि होगी। प्रसन्नता रहेगी। चोट व रोग से बचें। लेन-देन में जल्दबाजी न करें। किसी व्यक्ति के बहकावे में न आएं। व्यापार ठीक चलेगा। निवेश शुभ रहेगा। पारिवारिक सहयोग मिलेगा।

कुंभ: दूर से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। घर में मेहमानों का आगमन होगा। कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। आत्मविश्वास बढ़ेगा। जोखिम उठाने का साहस कर पाएंगे। व्यापार-व्यवसाय ठीक चलेगा। निवेश शुभ रहेगा। प्रसन्नता बनी रहेगी। चिंता तथा तनाव बने रहेंगे। यश बढ़ेगा।

मीन: व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी। रोजगार प्राप्ति के प्रयास सफल रहेंगे। निवेश शुभ रहेगा। व्यापार मनोनुकूल लाभ देगा। किसी बड़ी समस्या से मुक्ति मिल सकती है। किसी न्यायपूर्ण बात का भी विरोध हो सकता है। विवाद न करें।

‘सेफ फूड, सेफ महाराष्ट्र’ अभियान के तहत एफडीए की बड़ी कार्रवाई

मुंबई में 34 बेकरियों की जांच, 5 के लाइसेंस तत्काल निलंबित, 4 को कारोबार बंद करने का आदेश, राज्यभर में 4.05 लाख रुपये का खाद्य पदार्थ जब्त

संवाददाता

मुंबई। महाराष्ट्र के अन्न एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने खाद्य सुरक्षा आयुक्त तुकाराम मुंढे के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे ‘सेफ फूड, सेफ महाराष्ट्र’ विशेष अभियान के तहत गुरुवार को राज्यभर में बड़े पैमाने पर कार्रवाई करते हुए 61 होटल, रेस्तरां, ढाबों और बेकरी प्रतिष्ठानों की जांच की। इस दौरान 34 प्रतिष्ठानों को सुधार नोटिस, 6 खाद्य प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित तथा 4 प्रतिष्ठानों को तत्काल कारोबार बंद करने के आदेश जारी किए गए। साथ ही 4.05 लाख रुपये से अधिक मूल्य के खाद्य पदार्थ जब्त किए गए। एफडीए के अनुसार, 23 जुलाई 2026 को चलाए गए अभियान के दौरान मुंबई में 34 बेकरी प्रतिष्ठानों की विशेष जांच की गई। जांच के दौरान खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 और उससे जुड़े नियमों के गंभीर उल्लंघन पाए जाने पर 5 बेकरियों के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए गए, जबकि 4 बेकरियों को व्यवसाय बंद करने का नोटिस जारी किया गया। इसके अलावा

22 बेकरियों को सुधार नोटिस तथा 3 मामलों में कम्पाउंडिंग की कार्रवाई की गई।

पांच बेकरियों के लाइसेंस हुए निलंबित

एफडीए ने ब्रिस्टल बेकरी (माहीम), अनमोल बेकरी एंड स्टोर्स (अंधेरी पूर्व), न्यू महाराष्ट्र बेकरी एंड स्टोर (चेंबूर), साबा बेकरी एंड स्टोर्स (गोरेगांव पूर्व) तथा उन्नति बेकरी (दहिसर पश्चिम) के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए। वहीं बेंगलुरु अय्यंगार बेकरी (कालाचौकी), गोल्डन बेकरी (घाटकोपर पश्चिम), मिर्जा एंड सन्स बेकरी (विक्रोली पश्चिम) तथा बिग बाइट बेकरी (कांदिवली पूर्व) को कारोबार बंद करने के निर्देश दिए गए। एफडीए ने बताया कि कई प्रतिष्ठानों में बिना वैध पंजीकरण या लाइसेंस के खाद्य व्यवसाय संचालित किया जा रहा था। इसके अलावा स्वच्छता, खाद्य पदार्थों की हैंडलिंग और लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन भी पाया गया।

गुटखा-पान मसाला के खिलाफ भी कार्रवाई

राज्यभर में प्रतिबंधित गुटखा और पान मसाला की बिक्री, वितरण और परिवहन के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। इस दौरान एक मामला दर्ज कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया तथा 1,132 रुपये मूल्य का प्रतिबंधित माल जब्त किया गया। इसके अलावा अन्य खाद्य पदार्थों के 7,176.55 किलोग्राम वजन के 4.04 लाख रुपये मूल्य के खाद्य पदार्थ जब्त किए गए। कुल मिलाकर 4,05,352 रुपये का माल जब्त किया गया और 5 स्थानों पर छापेमारी की गई।

सांगली के होटल का लाइसेंस भी निलंबित

सांगली जिले के दिगंची स्थित होटल श्री प्योर वेज में जांच के दौरान स्वच्छता, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा नियमों के गंभीर उल्लंघन पाए जाने पर उसका खाद्य व्यवसाय लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।

अमरावती में गलत लेबल वाले टोस्ट जब्त

अमरावती में महाराष्ट्र बेकरी की जांच के दौरान इलायची फ्लेवर टोस्ट पर गलत लेबलिंग पाई गई। एफडीए ने 210 किलोग्राम टोस्ट का 22,990 रुपये मूल्य का स्टॉक जब्त कर लिया।

नवी मुंबई में फ्लैक्स सीड्स जब्त

नवी मुंबई के महापे स्थित अनादी एंटरप्राइजेज में खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के चलते 798 किलोग्राम फ्लैक्स सीड्स का लगभग 87,780 रुपये मूल्य का स्टॉक जब्त किया गया। संबंधित व्यापारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

पुणे में संदिग्ध गुणवत्ता का गुड़ जब्त

पुणे जिले के दौंड स्थित थिनविन्सिबल नैचरल फूड्स प्राइवेट लिमिटेड में जांच के दौरान 1,688.55 किलोग्राम गुड़ और गुड़ ट्रे संदिग्ध रूप से निकृष्ट गुणवत्ता और मिसब्रांडेड पाए गए। एफडीए ने 1,14,250 रुपये मूल्य का पूरा स्टॉक जब्त कर लिया। कोल्हापुर जिले के राधानगरी स्थित घाहिनीनाथ गुरहाल घर में बिना लेबल और बिना लाइसेंस के गुड़ तथा व्हाइट क्रिस्टल शुगर का कारोबार चलता मिला। यहां से 4,480 किलोग्राम खाद्य सामग्री, जिसकी कीमत 1,79,200 रुपये है, जब्त की गई। एफडीए को संदेह है कि यह खाद्य सामग्री निकृष्ट या असुरक्षित श्रेणी की हो सकती है। एफडीए ने सभी खाद्य व्यवसायियों से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 और उससे जुड़े नियमों का कड़ाई से पालन करने की अपील करते हुए स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ आगे भी इसी प्रकार की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

आदिवासी उत्पादों को मिले स्थायी बाजार, हर आदिवासी गांव बने आत्मनिर्भर: राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा

क्लस्टर विकास योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर, योजनाओं की सफलता लोगों की आय और जीवन स्तर से आंकी जाए

संवाददाता

मुंबई। महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने कहा है कि आदिवासी क्षेत्रों में तैयार होने वाले उत्पाद उच्च गुणवत्ता के होते हैं, लेकिन उनके प्रभावी और स्थायी विपणन की सबसे अधिक आवश्यकता है। उन्होंने अधिकारियों से आह्वान किया कि क्लस्टर विकास योजना का प्रभावी क्रियान्वयन कर प्रत्येक आदिवासी गांव को आत्मनिर्भर और आदर्श गांव बनाया जाए तथा वहां रहने वाले परिवारों के लिए स्थायी आजीविका के अवसर विकसित किए जाएं। शुक्रवार को राजभवन स्थित लोकभवन में अनुसूचित क्षेत्रों में समूह (क्लस्टर) विकास योजना की समीक्षा के लिए आदिवासी विकास विभाग के साथ आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक में राज्यपाल ने यह निर्देश दिए। बैठक में राज्यपाल के सचिव डॉ. प्रशांत नारनवरे, आदिवासी विकास विभाग के सचिव विजय वाघमारे, आयुक्त लीना बनसोड, आदिवासी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के आयुक्त निलेश सागर सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और परियोजना अधिकारी उपस्थित थे। राज्यपाल ने कहा कि आदिवासी क्षेत्रों में बांस, बेंत, आयुर्वेदिक उत्पाद, लघु वन

उपज सहित अनेक गुणवत्तापूर्ण उत्पाद तैयार किए जाते हैं, लेकिन इन उत्पादों की सबसे बड़ी चुनौती बाजार तक पहुंच है।

उन्होंने कहा कि प्रत्येक गांव की उत्पादन क्षमता, उपलब्ध बाजार और उत्पादकों को मिलने वाली आय का अध्ययन कर दीर्घकालिक विपणन नीति तैयार की जानी चाहिए। इसके साथ ही उत्पादों की आकर्षक पैकेजिंग और उनके लिए स्थायी बाजार उपलब्ध कराना भी उतना ही जरूरी है। उन्होंने कहा कि मुंबई जैसे विशाल बाजार का लाभ आदिवासी उत्पादों को दिलाने के लिए प्रभावी विपणन रणनीति बनाई जानी चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर कॉर्पोरेट कंपनियों के साथ साझेदारी कर आदिवासी उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने का प्रयास किया जाए।

राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) पर विशेष जोर देते हुए कहा कि बाजार की मांग के अनुसार नए उत्पाद विकसित किए जाएं। साथ ही आदिवासी परिवारों को पशुपालन, डेयरी, कुक्कुट पालन और मत्स्य पालन जैसे विविध आजीविका आधारित व्यवसायों के लिए प्रोत्साहित किया जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी योजना या परियोजना को शुरू करने से पहले संबंधित परिवार की आय का आकलन किया जाए और योजना लागू होने के बाद उसकी आय में कितना वास्तविक सुधार हुआ, इसका मूल्यांकन अनिवार्य रूप से किया जाए। योजनाओं की सफलता केवल उनकी संख्या से नहीं, बल्कि लोगों के जीवन में आए सकारात्मक बदलाव से मापी जानी चाहिए। राज्यपाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि केवल योजनाएं लागू करने तक सीमित न रहें, बल्कि यह भी सुनिश्चित करें कि इन योजनाओं से आदिवासी परिवारों की आय, जीवन स्तर, स्वास्थ्य, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य तथा आर्थिक स्थिति में कितना सुधार हुआ है। इन सभी पहलुओं की नियमित समीक्षा कर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाए।

बैठक में आदिवासी विकास विभाग के सचिव विजय वाघमारे ने बताया कि विभाग ने विभिन्न सरकारी विभागों के समन्वय से विस्तृत कार्ययोजना तैयार की है। इसके लिए पशुसंवर्धन, डेयरी, मत्स्य पालन और कृषि विभाग सहित संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित किया गया है।

उन्होंने कहा कि केवल योजना बनाकर ही नहीं, बल्कि आवश्यक परियोजनाओं के लिए बजटीय प्रावधान भी सुनिश्चित किए गए हैं। वहीं, आदिवासी विकास आयुक्त लीना बनसोड ने आदर्श आदिवासी गांव क्लस्टर योजना के तहत चयनित क्लस्टरों, वहां संचालित की जाने वाली गतिविधियों और भविष्य की कार्ययोजना की विस्तृत जानकारी प्रस्तुति के माध्यम से दी।

पनवेल में सिडको की बड़ी कार्रवाई

अवैध मलबा फेंकने के मामले में 17 डंपर चालकों समेत 18 के खिलाफ मामला दर्ज

संवाददाता

नवी मुंबई। सिडको ने अपनी अधिसूचित भूमि पर अवैध रूप से निर्माण मलबा फेंकने के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 17 डंपर चालकों और एक पोकलेन मशीन ऑपरेटर के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। यह कार्रवाई पनवेल के कुंडेवहल क्षेत्र में संयुक्त अभियान के दौरान की गई। हालांकि कार्रवाई के दौरान डंपर चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गए, जबकि पोकलेन मशीन को जब्त कर पनवेल सिटी पुलिस के हवाले कर दिया गया। यह संयुक्त अभियान गुरुवार को सिडको के इंजीनियरिंग विभाग, सतर्कता विभाग, सुरक्षा विंग तथा पनवेल सिटी पुलिस की टीम ने चलाया।

अधिकारियों के अनुसार, कार्रवाई सिडको के मुख्य सतर्कता अधिकारी सुरेश मेंगडे को मिली गुप्त सूचना के आधार पर की गई, जिसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए हानिकारक निर्माण मलबा अवैध रूप से फेंके जाने की जानकारी मिली थी। छापेमारी के दौरान टीम ने पाया कि 17 डंपर निर्माण मलबा खाली कर रहे थे, जबकि एक पोकलेन मशीन

उस मलबे को सिडको की अधिसूचित भूमि पर फैला रही थी। अधिकारियों ने जब चालकों से पूछताछ का प्रयास किया तो उन्होंने कथित रूप से कार्रवाई में बाधा डाली और अपने-अपने डंपर लेकर मौके से फरार हो गए। वहीं पोकलेन ऑपरेटर मशीन छोड़कर भाग निकला।

सिडको की शिकायत पर पनवेल सिटी पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धाराओं 271, 221, 352, 351(2) और 126(2) के तहत 17 अज्ञात डंपर चालकों और एक पोकलेन ऑपरेटर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने के प्रयास में जुटी है। सिडको के मुख्य सतर्कता अधिकारी सुरेश मेंगडे ने कहा कि संस्था ने अपनी भूमि पर अवैध रूप से मलबा फेंकने के मामलों में जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की गतिविधियां पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के साथ-साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए भी गंभीर खतरा उत्पन्न करती हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में शामिल लोगों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। सिडको ने नागरिकों से भी अपील की है कि यदि कहीं उसकी भूमि पर अवैध रूप से मलबा डाला जा रहा हो तो इसकी सूचना तत्काल सिडको या स्थानीय पुलिस को दें, ताकि समय रहते प्रभावी कार्रवाई की जा सके।

CM के वर्षा आवास और मंत्रालय में सुरक्षा बढ़ाई गई

संवाददाता

मुंबई। पुलिस द्वारा पूरे राज्य में सुरक्षा अलर्ट जारी किए जाने के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के सरकारी आवास 'वर्षा' और मंत्रालय में सुरक्षा काफी बढ़ा दी गई है।दिल्ली में हाल की घटनाओं को देखते हुए यह सतर्कता बढ़ाई गई है, जिससे अधिकारियों को पूरे महाराष्ट्र में एहतियाती उपाय बढ़ाने पड़े हैं। महत्वपूर्ण सरकारी ठिकानों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है, जबकि संवेदनशील जगहों पर सुरक्षा जांच तेज कर दी गई है। अधिकारियों ने कहा कि सुरक्षा के ये कड़े इंतजाम एहतियाती हैं और इनका

मकसद लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। पुलिस ने राज्य भर की फील्ड यूनिट्स को भी हाई अलर्ट पर रहने, संदिग्ध गतिविधियों पर नज़र रखने और महत्वपूर्ण सार्वजनिक व सरकारी परिसरों पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है।पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी लगातार सुरक्षा स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं और किसी भी संभावित खतरे से तुरंत निपटने के लिए विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच तालमेल बेहतर किया गया है। अधिकारियों ने नागरिकों से सतर्क रहने, सुरक्षा कर्मियों का सहयोग करने और किसी भी संदिग्ध वस्तु या गतिविधि की सूचना तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन या इमरजेंसी हेल्पलाइन को देने की अपील की है।सुरक्षा के लिए की गई यह अतिरिक्त तैनाती तब तक जारी रहेगी जब तक राज्य प्रशासन की ओर से कोई और निर्देश नहीं दिया जाता।

बीएमसी का सख्त अभियान, एक दिन में 640 अवैध बैनर-पोस्टर हटाए गए

संवाददाता

मुंबई। बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) ने बिना इजाज़त लगाए गए आउटडोर विज्ञापनों के खिलाफ़ अपनी कार्रवाई तेज़ कर दी है। शहर भर में चलाए गए एक अभियान के तहत, एक ही दिन में मुंबई और उसके उपनगरों से 640 गैर-कानूनी बैनर और पोस्टर हटाए गए।नगर निकाय के एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, यह ऑपरेशन BMC के लाइसेंस विभाग ने अतिरिक्त नगर आयुक्त (पश्चिमी उपनगर) डॉ. विपिन शर्मा के निर्देशों और उप नगर आयुक्त (विशेष) विनायक विस्पुते की देखरेख में चलाया। हटाए गए

640 गैर-कानूनी विज्ञापनों में से 336 राजनीतिक बैनर थे, जो सबसे बड़ी श्रेणी थी। नगर निकाय ने धार्मिक हस्तियों और कार्यक्रमों से जुड़े 186 धार्मिक बैनर और पोस्टर भी हटाए, जबकि 118 कमर्शियल विज्ञापन भी हटाए गए।यह विशेष अभियान बुधवार को शुरू हुआ और यह BMC के उस अभियान का हिस्सा है जिसके तहत मुंबई भर में सार्वजनिक जगहों से गैर-कानूनी होर्डिंग, बैनर और पोस्टर हटाए जा रहे हैं। BMC ने नागरिकों, सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों से अपील की है कि वे नगर निकाय से पहले से इजाज़त लिए बिना सड़कों, फुटपाथों या अन्य सार्वजनिक जगहों पर बैनर, होर्डिंग या पोस्टर न लगाएं।अधिकारियों ने बताया कि लाइसेंस विभाग नियमित रूप से निरीक्षण करता है और नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए गैर-कानूनी विज्ञापनों के खिलाफ़ कार्रवाई करता है। BMC के अनुसार, हर साल लगभग 15,000 से 20,000 गैर-कानूनी होर्डिंग, बैनर और पोस्टर हटाए जाते हैं, जिनमें से लगभग 45% राजनीतिक जन्मदिन की शुभकामनाओं और त्योहारों के जश्न से जुड़े होते हैं। इस बार-बार होने वाली समस्या से निपटने के लिए, नगर निकाय ने पिछले साल अपनी आउटडोर विज्ञापन प्रदर्शन नीति शुरू की थी, जिसके तहत सभी आउटडोर विज्ञापनों के लिए पहले से लिखित इजाज़त लेना ज़रूरी कर दिया गया है। नियम तोड़ने वालों पर बृहन्मुंबई नगर निगम अधिनियम, 1888 की धारा 471 और महाराष्ट्र संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 1995 के तहत कार्रवाई हो सकती है।

विदेशी मुद्रा भंडार में 1.08 अरब डॉलर की बढ़ोतरी, 676.24 अरब डॉलर पहुंचा रिजर्व; अर्थव्यवस्था को मिली मजबूती: आरबीआई

संवाददाता

मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार (फॉरेक्स रिजर्व) 17 जुलाई को समाप्त सप्ताह में 1.08 अरब डॉलर बढ़कर 676.237 अरब डॉलर पर पहुंच गया। इससे पहले वाले सप्ताह में भी विदेशी मुद्रा भंडार में 964 मिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हुई थी और यह 675.157 अरब डॉलर पर पहुंच गया था। इस तरह, लगातार दूसरे सप्ताह देश के विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आरबीआई की

वीकली स्टैटिस्टिकल सप्लीमेंट के मुताबिक, इस वर्ष की शुरुआत में वैश्विक अनिश्चितताओं के कारण आई गिरावट के बाद भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार मजबूत हो रहा है। इससे पहले 27 फरवरी को समाप्त सप्ताह में देश का विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड 728.494 अरब डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया था। आंकड़ों के अनुसार, विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा हिस्सा मानी जाने वाली विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां (फॉरेन करेंसी एसेट्स) 4.549 अरब डॉलर बढ़कर 551.057 अरब डॉलर हो गईं। डॉलर के संदर्भ में इन परिसंपत्तियों के मूल्य पर यूरो, पाउंड और येन जैसी गैर-अमेरिकी मुद्राओं में होने वाली बढ़त या गिरावट का भी प्रभाव पड़ता है। वहीं, देश के स्वर्ण भंडार (गोल्ड रिजर्व) का मूल्य 3.48 अरब डॉलर घटकर 101.749 अरब डॉलर रह गया। इसके अलावा, विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) 44 मिलियन डॉलर बढ़कर 18.67 अरब डॉलर पर पहुंच गए। आरबीआई ने बताया कि विदेशी मुद्रा भंडार में विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, स्वर्ण भंडार, विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) में भारत की रिजर्व ट्रेंच पोजीशन शामिल होती है। यह भंडार बाहरी आर्थिक झटकों से देश की सुरक्षा करने, रुपए की स्थिरता बनाए रखने और आयात तथा अन्य बाहरी भुगतान दायित्वों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रिपोर्ट के अनुसार, पश्चिम एशिया में बढ़े तनाव के दौरान रुपए पर दबाव बढ़ने के कारण आरबीआई ने डॉलर बेचकर विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप किया था, जिससे कुछ सप्ताह तक विदेशी मुद्रा भंडार पर असर पड़ा। हालांकि अब इसमें फिर से सुधार देखने को मिल रहा है।

Karnataka Dy CM Parameshwara urges PM Modi to scrap NEET, Restore State CETs

BENGALURU: Karnataka Deputy Chief Minister G. Parameshwara has urged Prime Minister Narendra Modi to roll back the National Eligibility-cum-Entrance Test (NEET) and restore transparent, merit-based Common Entrance Tests (CETs) conducted by individual States for medical admissions, arguing that such a move would uphold India's federal structure and address growing concerns over the credibility of the examination system. In a letter to the Prime Minister, copies of which were released to the media on Thursday, Dr. Parameshwara said repeated controversies surrounding NEET, including the paper leak scandal and allegations of systemic failures, had severely undermined public confidence in the country's education system. He said there was widespread anxiety among students, parents, educators and employers over the declining credibility of competitive examinations and the

quality of higher education.

The Deputy Chief Minister appealed to the Centre to provide compensation of at least ₹1 crore to the families of students who allegedly died by suicide in the aftermath of the NEET paper leak and related institutional failures. He also sought adequate compensation for students and citizens who sustained injuries during police action, including lathi-charge and tear gas shelling, while participating in protests against the examination.

Calling for accountability, Dr. Parameshwara urged the Prime Minister to order an impartial inquiry into the incidents and ensure strict action against those responsible for the use of force against peaceful demonstrators. He also called for a meaningful dialogue with students, educators, academic institutions and other stakeholders to undertake comprehensive reforms to the examination system.

Expressing concern over the handling of student protests, Dr. Parameshwara said images of students being dispersed through police action had deeply disturbed citizens across the country. He also referred to the response to environmental activist Sonam Wangchuk's peaceful hunger strike, saying it had reinforced concerns that democratic dissent was increasingly being treated as an inconvenience rather than an essential part of public discourse. He warned that every paper leak, institutional failure and unanswered question further erodes trust in India's education system and weakens the country's global academic reputation.

Paper Leak Cases Need Proof, Not Just Fast-Track Courts: Kejriwal

NEW DELHI: Aam Aadmi Party (AAP) National Convenor and former Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal on Friday questioned Prime Minister Narendra Modi's assurance of introducing a law to establish fast-track courts for paper leak cases, describing the proposal as hollow. He alleged that if the investigating agency fails to present sufficient evidence before the courts, the creation of fast-track courts would serve little purpose.

In a statement issued on Friday, Kejriwal said that while the Prime Minister had spoken about setting up fast-track courts for the speedy trial of paper leak cases, reports had emerged that the Central Bureau of Investigation (CBI) had informed the court that it had not found sufficient

evidence against Sanjeev Mukhia in the NEET paper leak case.

He questioned that if Sanjeev Mukhia was not the alleged mastermind, then who was the real mastermind behind the paper leak. He further asked that if there was no mastermind, how such a large-scale paper leak could have taken place.

Kejriwal alleged that if government investigating agencies fail to place credible evidence before the courts, even fast-track courts would not be effective. He said that if the government's intentions were sincere, it would conduct a strong investigation and ensure stringent punishment for those accused in the paper leak cases. He said that students across the country had been adversely affected by repeated paper leak incidents and that the government should take concrete measures to prevent such occurrences in the future.

Kejriwal further asserted that merely announcing the establishment of fast-track courts would not solve the problem unless the investigation and prosecution processes were made effective.

He added that the government must ensure transparency in competitive examinations and take strict action against those responsible so that the confidence of candidates in the examination system is restored.

ODISHA : MOUS SIGNED WITH HCLTECH AND SARVAM AI IN PRESENCE OF CM

BHUBANESWAR: Marking a major leap in Odisha's industrial and technology landscape, Chief Minister Mohan Charan Majhi on Friday announced the beginning of a 'new tech revolution' in the state following the signing of two landmark Memoranda of Understanding (MoUs) with HCLTech and Sarvam AI.

The agreements were signed at the Lok Seva Bhawan Convention Centre and are expected to significantly boost technology-driven economic growth while creating large-scale employment opportunities for the state's skilled youth. Under the collaboration, HCLTech will establish a Global Delivery Centre in Odisha with an investment of approximately ₹730 crore. The project is expected to generate direct employment for over 6,000 highly educated and skilled youths. In addition, a state-of-the-art AI-optimised Data Centre will be set up through a joint initiative between HCLTech and Sarvam AI.

The state government will also develop a sovereign AI Park, within which the proposed data centre will be located. Overall,

the two projects are projected to attract investments of around ₹15,000 crore over the next five years. Speaking on the occasion, the Chief Minister credited Prime Minister Narendra Modi's 'Digital India' vision for making the country tech-ready, adding that Odisha is emerging as a frontrunner in this transformation. He noted that indigenous AI platform Sarvam is now capable of competing with global technologies and will be widely deployed across sectors such as agriculture, healthcare, education, and defence. Highlighting the state's industrial progress, Majhi said Odisha has received investment proposals exceeding ₹20 lakh crore in the past two years, with projects worth over ₹10 lakh crore approved and more than ₹3 lakh crore already under implementation. He further stated that Odisha ranks among the top five states in the NITI Aayog Investment Friendliness Index-2026, with a target to enter the top three soon. Electronics and IT Minister Mukesh Mahaling described the development as a proud moment for the state, stating that it will propel Odisha's electronics and IT sectors to new heights.

HCLTech Chairperson Roshni Nadar Malhotra expressed confidence in Odisha's investment ecosystem and announced plans to expand the company's footprint in the state. She said the proposed AI Park would serve as a key milestone in advancing artificial intelligence capabilities.

Senior officials, including Additional Chief Secretary Vishal Kumar Dev, HCLTech CEO & MD C. Vijayakumar, and Sarvam AI CEO Pratyush Kumar, along with industry leaders and government representatives, were present at the event. The initiative is being seen as a transformative step towards positioning Odisha as a leading technology and innovation hub in India.

दक्षिण चीन समुद्रात पुन्हा तणाव: चीनकडून फिलिपिन्सच्या नौकांवर पाण्याचे फवारे

मनिला: फिलिपिन्सने शुक्रवारी सांगितले की, दक्षिण चीन समुद्रात चीनच्या तटरक्षक दलाच्या जहाजांनी त्यांच्या मत्स्य विभागाच्या दोन नौकांवर उच्च दाबाने पाण्याचे फवारे मारले. या आठवड्यात वादग्रस्त सागरी क्षेत्रात दोन्ही देशांमध्ये झालेली ही तिसरी मोठी चकमक आहे.

ही घटना अशा वेळी घडली आहे, जेव्हा मनिला येथे आशियाई आणि पाश्चिमात्य देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांची बैठक सुरू आहे. या बैठकीत चीनच्या सागरी हालचालींबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे.

फिलिपिन्सच्या तटरक्षक दलाच्या माहितीनुसार, ही घटना स्कारबोरो शोलजवळ घडली. चीनच्या एका तटरक्षक जहाजाने सरकारी मत्स्य विभागाच्या बीआरपी दातुक्स पडुहिनोग या नौकेपासून केवळ सात मीटर अंतर राखले होते.

फिलिपिन्सने म्हटले की, चीनने अत्यंत बेफिकिरीने ही कारवाई केली असून त्यामुळे दोन्ही जहाजांमध्ये धडक होण्याचा गंभीर धोका निर्माण झाला होता.फिलिपिन्सच्या तटरक्षक

दलाने चीनच्या या कारवाईचा तीव्र निषेध केला. त्यांनी सांगितले की, स्कारबोरो शोल हा फिलिपिन्सचा अविभाज्य भाग असून त्याच्या आसपासचा सागरी परिसर देशाच्या प्रादेशिक सीमांचा आणि विशेष आर्थिक क्षेत्राचा (EEZ) भाग आहे. तटरक्षक दलाच्या म्हणण्यानुसार, गुरुवारीदेखील स्कारबोरो शोलजवळ मत्स्य विभागाच्या दोन नौकांना चीनच्या तटरक्षक जहाजांनी अडथळे निर्माण केले होते. यावेळी एका नौकेवर उच्च दाबाचा पाण्याचा फवारा मारण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता.दुसरीकडे, चीनच्या तटरक्षक दलाने पुन्हा एकदा स्कारबोरो शोलवरील आपला सार्वभौम हक्क असल्याचा दावा केला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, त्या भागात बेकायदेशीररीत्या कार्यरत असलेल्या फिलिपिन्सच्या अनेक जहाजांविरुद्ध त्यांनी नियंत्रणात्मक कारवाई केली. चीन जवळपास संपूर्ण दक्षिण चीन समुद्रावर आपला दावा सांगतो. मात्र, २०१६ मधील आंतरराष्ट्रीय लवादाच्या निर्णयात हा दावा फेटाळण्यात आला होता. दशकांपासून सुरू असलेल्या या सागरी वादावर दक्षिण-पूर्व आशियाई राष्ट्रांच्या संघटनेच्या (आसियान) तसेच आशियाई आणि पाश्चिमात्य देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांच्या तीन दिवसीय बैठकीतही चर्चा झाली. ही बैठक मंगळवारपासून मनिला येथे बंद दरवाजांआड सुरू आहे. यामध्ये पश्चिम आशिया आणि युक्रेनमधील संघर्षांवरही चर्चा करण्यात आली. आसियानच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी मंगळवारी दक्षिण चीन समुद्रातील वादावर सविस्तर चर्चा केली. संयुक्त निवेदनात नमूद करण्यात आले की, काही देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी समुद्रात कृत्रिम भूभाग निर्माण करणे, वादग्रस्त कारवाया, गंभीर घटना, लोकांच्या सुरक्षिततेला धोका निर्माण करणाऱ्या कृती आणि सागरी पर्यावरणाचे होणारे नुकसान याबाबत चिंता व्यक्त केली.

कारवर दरड कोसळून 13 जणांचा मृत्यू

शिमला: हिमाचल प्रदेशच्या लाहोल-स्पीती जिल्ह्यात आज, शुक्रवारी दुपारी भीषण दुर्घटना घडली. तिंदीहून पांगीकडे जात असलेल्या टाटा सूमो टॅक्सीवर अचानक डोंगरावरील भली मोठी दरड कोसळल्याने वाहन चिरडले गेले. या भीषण अपघातात 13 जणांचा मृत्यू झाल्याची प्राथमिक माहिती प्रशासनाने दिली आहे.

प्रशासनाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार उदयपूर-किलाड (तांदी-संसारी राष्ट्रीय महामार्ग) मार्गावरील कडू नाला परिसरात हा अपघात घडला. अपघातग्रस्त टाटा सूमो (क्रमांक : एचपी-01एम-2210) कुल्लूहून पांगीकडे जात होती. वाहनात चालकासह सुमारे 14 प्रवासी असल्याचे सांगितले जात आहे.मागील दिवशी मुसळधार पावसामुळे आणि दरड कोसळल्याने उदयपूर-किलाड मार्ग वाहतुकीसाठी बंद होता. त्यामुळे सर्व प्रवासी तिंदी येथे थांबले होते. शुक्रवारी मार्ग सुरू झाल्यानंतर वाहन पांगीकडे रवाना झाले. मात्र, कडू नाला परिसरात अचानक डोंगराचा मोठा भाग कोसळून प्रचंड दगड आणि मलबा वाहनावर पडल्याने ही दुर्घटना घडली.

जंतर-मंतर आंदोलनापासून दूर राहण्याच्या सूचनेवरून राहुल गांधींची दिल्ली विद्यापीठावर टीका

नवी दिल्ली : लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी शुक्रवारी दिल्ली विद्यापीठाच्या (डीयू) त्या सल्लागार सूचनेवर (ॲडव्हायजरी) तीव्र टीका केली, ज्यामध्ये विद्यार्थ्यांना जंतर-मंतर येथे सुरू असलेल्या आंदोलनांपासून दूर राहण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. काँग्रेस नेत्याने विद्यापीठावर विद्यार्थ्यांना त्यांच्या लोकशाही हक्कांचा वापर करण्यापासून रोखण्यासाठी आणि त्यांना धमकावण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केला. दिल्ली विद्यापीठाच्या ॲडव्हायजरीवर प्रतिक्रिया देताना राहुल गांधी यांनी 'एक्स' या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर लिहिले, 'विद्यार्थ्यांना त्यांच्या लोकशाही हक्कांचा वापर केल्याबद्दल धमकावण्याचे धाडस तुम्ही कसे करू शकता? हे लक्षात ठेवा, योग्य वेळी तुम्हालाच याचे उत्तर द्यावे लागेल.' दिल्ली विद्यापीठाने जारी केलेल्या सुरक्षा सल्लागार सूचनेत विद्यार्थी आणि प्राध्यापकांना कथित नीट-यूजी प्रश्नपत्रिका फुटीच्या निषेधार्थ सुरू असलेल्या आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर जंतर-मंतर येथे होणाऱ्या बेकायदेशीर

सभा किंवा आंदोलनांपासून दूर राहण्याचे आवाहन केले होते.

ॲडव्हायजरीमध्ये विद्यापीठाने म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार जंतर-मंतर येथील आंदोलने आणि निदर्शने कडक नियंत्रणाखाली असतात.

तसेच, बेकायदेशीर सभा किंवा आंदोलनांमध्ये सहभागी झाल्यास संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते, असा इशाराही देण्यात आला आहे. याशिवाय, अशा प्रकारच्या कृतींमुळे विद्यार्थ्यांच्या वैयक्तिक सुरक्षेला धोका निर्माण होऊ शकतो आणि त्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीवर तसेच भविष्यातील व्यावसायिक संधींवरही विपरीत परिणाम होऊ शकतो, असे विद्यापीठाने नमूद केले आहे. त्यामुळे सर्व विद्यार्थ्यांनी जंतर-मंतरपासून दूर राहून स्वतःची सुरक्षा आणि कायद्याचे पालन यांना प्राधान्य द्यावे, असे आवाहन करण्यात आले. दिल्ली विद्यापीठाने विद्यार्थ्यांना दिशाभूल करणाऱ्या माहितीपासून सावध राहण्याचाही सल्ला दिला आहे. परिस्थिती चिघळवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर बनावट आणि भ्रामक माहिती तयार करून प्रसारित केली जात असल्याचे विद्यापीठाने म्हटले असून, कोणतीही माहिती सत्यता पडताळून न पाहता तिच्यावर विश्वास ठेवू नये किंवा ती पुढे पाठवू नये, असे आवाहन करण्यात आले आहे. राहुल गांधी यांची ही टीका अशा वेळी समोर आली आहे, जेव्हा त्यांनी एक दिवस आधी 'इंडिया' आघाडीतील इतर नेत्यांसह कथित नीट-यूजी प्रश्नपत्रिका फुटीविरोधात आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या समर्थनार्थ गांधी स्मृतीपर्यंत मोर्चा काढण्याचा प्रयत्न केला होता.विरोधकांच्या म्हणण्यानुसार, या मोर्च्याचा उद्देश या वादानंतर आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांना श्रद्धांजली वाहणे तसेच आंदोलनादरम्यान जखमी झालेल्या व्यक्तींप्रती ऐक्य आणि समर्थन व्यक्त करणे हा होता.

अमेरिका-इराण संघर्ष तीव्र: अमेरिकेचा इराणवर सलग १३व्या रात्री हल्ला

वॉशिंग्टन: होर्मुझ सामुद्रधुनीवरील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिका आणि इराण यांच्यातील लष्करी संघर्ष अधिक तीव्र होत चालला आहे. अमेरिकन सैन्याने गुरुवारी सलग १३व्या रात्री इराणवर हल्ले केले.

त्याचवेळी,यमनमधील इराणसमर्थक हूती बंडखोरांनी लाल समुद्रात सौदी अरेबियाच्या दोन तेलवाहू टँकरांना लक्ष्य केल्याचा दावा केला आहे.

या घटनांमुळे संपूर्ण पश्चिम आशियात संघर्ष आणखी विस्तारण्याची भीती वाढली आहे.या घडामोडींचा परिणाम जागतिक बाजारावरही दिसून आला असून, आंतरराष्ट्रीय बाजारात ब्रेंट क्रूड तेलाची किंमत प्रति बॅरल १०० डॉलर्सच्या पुढे गेली आहे. अमेरिकेच्या सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने सांगितले की, ताज्या हल्ल्यांचा उद्देश इराणची ती क्षमता कमकुवत करणे हा आहे, ज्याच्या माध्यमातून तो प्रादेशिक समुद्री क्षेत्रातून जाणाऱ्या व्यापारी जहाजे आणि नाविकांसाठी धोका निर्माण करत आहे. अमेरिकेचे म्हणणे आहे की,होर्मुझ सामुद्रधुनीतील आंतरराष्ट्रीय जलवाहतूक सुरक्षित आणि सुरळीत करण्यासाठी हे प्रयत्न सुरू आहेत. अमेरिकन हल्ल्यांनंतर

काही वेळातच इराणच्या सरकारी माध्यमांनी होर्मुझ सामुद्रधुनीजवळील बंदर अब्बास आणि केश्म बेट परिसरात स्फोट झाल्याची माहिती दिली. याशिवाय, उत्तर-पश्चिमेकडील अँडिमेश्क आणि ओमिदियेह परिसरातही स्फोट झाल्याच्या बातम्या समोर आल्या. मात्र, या स्फोटांमुळे झालेल्या नुकसानीबाबत अद्याप अधिकृत माहिती जाहीर करण्यात आलेली नाही. दरम्यान, हूती बंडखोरांनी आणखी एका महत्त्वाच्या सागरी व्यापारी मार्गात अडथळा निर्माण करण्याची धमकी दिली आहे. इराणकडून होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद करण्यात आल्याने आधीच जागतिक व्यापार आणि ऊर्जा पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे. सामान्य परिस्थितीत जगातील सुमारे २० टक्के तेल आणि नैसर्गिक वायूचा पुरवठा या समुद्री मार्गातून होतो. त्यामुळे अनेक देश पर्यायी जहाजवाहतूक मार्गांचा शोध घेत आहेत. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, जहाजांवरील हल्ले सुरूच राहिल्यास हूती बंडखोरांना 'कठोर लष्करी शिक्षा' दिली जाईल. त्यांनी सामाजिक माध्यमांवर लिहिले की, भविष्यात असे हल्ले पुन्हा झाल्यास अमेरिका त्यासाठी थेट इराणला जबाबदार धरेल, कारण हूती संघटना इराणच्या पाठबळावर कार्य करते. ट्रम्प यांनी इशारा दिला की, इराण आणि हूती या दोघांनाही याचे गंभीर लष्करी परिणाम भोगावे लागतील.

मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ

म्हाडा MHADA

(म्हाडाचा घटक)

जाहिर सुचना

मौजे- वांद्रे, ता-अंधेरी येथील न.भू.क्र.३० (पै) या मिळकतीवरील बच्चीदेवी चाळ सह. गृह. संस्था (नियो.) या संस्थेच्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेअंतर्गत परि-२ मधील अ.क्र. १३१ वरील अपात्र झोपडीधारक श्री. मोहम्मद युसूफ खान यांचा पात्रता निश्चित करणेकामीचा अर्ज प्राप्त झाला आहे. सबब सदर नोटीसीद्वारे कळविण्यात येते की, उपरोक्त प्रकरणी हरकत अंसल्यास ८ दिवसांत खालील सही करणार यांच्या कार्यालयात लेखी स्वरूपात नोंदविण्यात याव्यात. मुदतीनंतर प्राप्त हरकती विचारात घेतल्या जाणार नाही, याची कृपया नोंद घ्यावी, असे याद्वारे जाहिर असे.

पत्ता : कक्ष क्र.३११, दुसरा मजला, गृहनिर्माण भवन, कलानगर, वांद्रे (पूर्व), मुंबई -४०० ०५१

करीता/ - सक्षम प्राधिकारी तथा भूव्यवस्थापक मुंबई मंडळ

ठिकाण : मुंबई

दिनांक : २५/०७/२०२६

म्हाडा- गृहनिर्माण क्षेत्रातील देशातील अग्रगण्य संस्था

कुणाल कामरा विवाद पर मन्नारा की दो टूक

मुंबई। अभिनेत्री मन्नारा चोपड़ा ने कॉमेडियन कुणाल कामरा के जंतर-मंतर पर दिए गए बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि किसी भी सार्वजनिक मंच का उद्देश्य मूल मुद्दों पर चर्चा होना चाहिए। उनके अनुसार, यदि कार्यक्रम छात्रों से जुड़े विषयों के लिए आयोजित किया गया है तो बहस भी उसी तक सीमित रहनी चाहिए। मन्नारा ने कहा कि किसी विशेष धर्म या विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए ऐसे मंचों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। उनका मानना है कि चर्चा का केंद्र केवल वही विषय होना चाहिए, जिससे कार्यक्रम का सीधा संबंध हो।

उन्होंने कहा कि अनावश्यक रूप से दूसरे मुद्दों या व्यक्तियों को बहस का हिस्सा बनाने से मूल उद्देश्य प्रभावित होता है। मन्नारा ने यह भी स्पष्ट किया कि वह अन्य लोगों के निजी मामलों या उनकी टिप्पणियों पर अपनी राय देना उचित नहीं समझतीं। उनके अनुसार, छात्रों से जुड़े मुद्दे सबसे महत्वपूर्ण हैं और ध्यान उसी दिशा में रहना चाहिए।

दरअसल, दिल्ली के जंतर-मंतर पर सोनम वांगचुक के समर्थन में आयोजित एक प्रदर्शन के दौरान स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने केंद्र सरकार पर टिप्पणी की थी। उनके बयान के बाद विवाद खड़ा हो गया और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की एक अधिवक्ता की ओर से उन्हें कानूनी नोटिस भी भेजा गया।

मन्नारा चोपड़ा ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत वर्ष 2014 में तेलुगु फिल्म 'प्रेमा गीमा जंथा नाई' से की थी। इसके बाद उन्होंने फिल्म 'जिद' से बॉलीवुड में कदम रखा। साल 2023 में रियलिटी शो 'बिग बॉस 17' में हिस्सा लेने के बाद उन्हें व्यापक लोकप्रियता मिली, जहां वह दूसरे रनर-अप के रूप में उभरीं।

'रामायण' मेरी बेटी राहा की बड़े पर्दे पर पहली फिल्म होगी : रणबीर कपूर

मुंबई। अभिनेता रणबीर कपूर ने अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'रामायण' को अपने करियर का सबसे खास और यादगार प्रोजेक्ट बताया है। सैन डिएगो कॉमिक-कॉन (एसडीसीसी) में निर्माता नमित मल्होत्रा, निर्देशक नितेश तिवारी और अभिनेता यश के साथ पहुंचे रणबीर ने फिल्म से जुड़ा एक भावुक खुलासा किया। उन्होंने कहा कि 'रामायण' उनकी दो वर्षीय बेटी राहा कपूर की बड़े पर्दे पर देखी जाने वाली पहली फिल्म होगी। रणबीर ने कहा, मैं इसे लेकर बेहद उत्साहित हूं। यह हमारे परिवार के लिए भी बहुत खास पल होगा।

रणबीर ने बताया कि जब उन्हें भगवान राम का किरदार निभाने का प्रस्ताव मिला था, तब उनके मन में कई सवाल और आशंकाएं थीं। उन्होंने कहा, मैं सोच रहा था कि क्या मैं इस

किरदार के साथ न्याय कर पाऊंगा? क्या मैं इसके योग्य हूं? लेकिन धीरे-धीरे वह डर कृतज्ञता में बदल गया। मुझे एहसास हुआ कि यह जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर और एक बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि 'रामायण' केवल एक फिल्म नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और आस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसलिए इसे पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ बनाया जा रहा है।

रणबीर ने भगवान राम को साहस, करुणा, क्षमा और धर्म का प्रतीक बताते हुए कहा कि करोड़ों लोग सदियों से उनके आदर्शों से प्रेरणा लेते आए हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि फिल्म हर पीढ़ी के दर्शकों से भावनात्मक रूप से जुड़ेगी। नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही इस महागाथा का पहला भाग दिवाली 2026 और दूसरा भाग दिवाली 2027 में रिलीज होगा। फिल्म में रणबीर कपूर के साथ यश, साई पल्लवी, सनी देओल, रवि दुबे, अरुण गोविल, लारा दत्ता, विवेक ओबेरॉय, रकुल प्रीत सिंह और कुणाल कपूर भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे।

'द इंडिया स्टोरी' की स्क्रीनिंग में काजल-श्रेयस का जलवा

मुंबई। काजल अग्रवाल और श्रेयस तलपड़े अभिनीत फिल्म 'द इंडिया स्टोरी' की रिलीज़ से पहले मुंबई में इसकी भव्य ग्रीन कार्पेट स्क्रीनिंग आयोजित की गई। इस खास मौके पर फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई कलाकार, मीडिया प्रतिनिधि और विशेष मेहमान शामिल हुए, जिन्होंने फिल्म का पहला प्रदर्शन देखा।

ग्रीन कार्पेट पर काजल अग्रवाल अपने स्टाइलिश अंदाज़ में नजर आईं, जबकि श्रेयस तलपड़े ने मेहमानों और मीडिया से आत्मीयता के साथ बातचीत की। दोनों कलाकारों ने कहा कि यह फिल्म सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज को एक महत्वपूर्ण संदेश देने का प्रयास भी करती है।

ज़ी स्टूडियोज़ और एमआईजी प्रोडक्शन एंड स्टूडियोज़ के बैनर तले बनी 'द इंडिया स्टोरी' में खाद्य पदार्थों में मिलावट और खेती में कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग जैसे गंभीर विषयों को प्रमुखता से उठाया गया है। फिल्म दर्शकों को यह सोचने पर मजबूर करती है कि रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाला भोजन कितना सुरक्षित है और उसका स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ सकता है।

स्क्रीनिंग के दौरान फिल्म जगत की कई जानी-मानी हस्तियों ने फिल्म के विषय और उसके सामाजिक संदेश की सराहना की। उपस्थित मेहमानों ने माना कि इस तरह के संवेदनशील मुद्दों को बड़े पर्दे पर प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना समय की जरूरत है।

चेतन डीके के निर्देशन में बनी इस फिल्म की कहानी और पटकथा सागर बी. शिंदे ने लिखी है और उन्होंने ही इसका निर्माण भी किया है। फिल्म में काजल अग्रवाल और श्रेयस तलपड़े मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे।

स्क्रीनिंग के बाद मिली सकारात्मक प्रतिक्रियाओं ने फिल्म को लेकर दर्शकों की उत्सुकता और बढ़ा दी है। 'द इंडिया स्टोरी' 24 जुलाई 2026 से देश और दुनिया के सिनेमाघरों में रिलीज़ हो चुकी है।

तेज धूप में भी बाल रहेंगे मुलायम और चमकदार, अपनाएं ये उपाय

मानसून के दौरान कहीं तेज धूप तो कहीं बारिश का दौर जारी है। ऐसे बदलते मौसम में बालों को धूल, पसीना, नमी और प्रदूषण का एक साथ सामना करना पड़ता है, जिससे वे रूखे, चिपचिपे, बेजान और कमजोर हो सकते हैं। इसलिए जैसे हम मौसम के अनुसार अपनी स्किनकेयर और ड्रेसिंग में बदलाव करते हैं, वैसे ही हेयर केयर रूटीन में भी बदलाव करना जरूरी है। सही देखभाल और कुछ आसान आदतों को अपनाकर इस मौसम में भी बालों को स्वस्थ, मजबूत और चमकदार रखा जा सकता है।

इन टिप्स से आएगी बालों में चमक

- गर्मी में पसीना आने की वजह से लोग रोजाना बाल धोने लगते हैं, लेकिन ऐसा करने से स्कैल्प का नेचुरल ऑयल खत्म हो जाता है। इससे बाल और ज्यादा ड्राई व फ्रिजी हो सकते हैं।
- आपको हफ्ते में 2-3 बार ही बालों को धोना चाहिए। इसके लिए माइल्ड शैंपू या हर्बल शैंपू का इस्तेमाल करें।
- अगर आपके बाल जल्दी फ्रिजी हो जाते हैं, तो शैंपू के बाद कंडीशनर लगाना बेहद जरूरी है। कंडीशनर बालों में नमी बनाए रखने में मदद करता है और उन्हें स्मूद बनाता है। खासतौर पर बालों की लंबाई और सिरों पर इसे जरूर लगाएं।
- कई बार जल्दबाजी में हम सिर्फ शैंपू

कर लेते हैं और कंडीशनर नहीं करते हैं, लेकिन यह सही नहीं है। कंडीशनर बालों को मॉइश्चर देता है और धूप से होने वाले डैमेज से बचाता है।

ऑयलिंग है सबसे जरुरी

सर्दी हो या गर्मी बालों में ऑयल मसाज करना बहुत जरुरी है। जैतून के तेल, नारियल के तेल या मीठे बादाम के तेल से मालिश करने से स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और आपके बाल पूरी तरह से मॉइश्चराइज रहते हैं। आप अपने नियमित तेल में लैवेंडर ऑयल की कुछ बूंदों को मिलाकर अप्लाई कर सकती हैं।

तौलिए में बालों को लपेटना

नहाने के बाद बहुत से लोगों की आदत होती है कि वे एक-देढ़ घंटे तक बालों में तौलिया बांधे घूमते रहते हैं। ऐसा करने पर बाल कमजोर हो जाते हैं। नहाने वाले तौलिया से बालों को पोंछने से बाल टूटते हैं।

बालों को टाइट बांधना

गर्मी के सीजन में बालों को बांध कर रखने के चक्कर में कई बार महिलाएं बालों को बहुत ज्यादा टाइट बांध लेती हैं, लेकिन बालों को टाइट बांधने से या कस कर जूड़ा या पोनीटेल बनाने से बालों की जड़ें कमजोर होने लगती हैं और हेयर फॉल हो सकता है। इसलिए बालों को हमेशा ढीला ही बांधना चाहिए।

हेयर मास्क और प्राकृतिक पैक का इस्तेमाल

सप्ताह में एक बार दही, अंडा, मेथी, एलोवेरा या केले का हेयर मास्क लगाएं। ये बालों को गहराई से पोषण और नमी देते हैं। ऐसे मास्क बालों की ड्रायनेस कम करते हैं और दोमुंहे होने से रोकते हैं। यूवी प्रोटेक्शन है जरुरी सूरज की हानिकारक किरणें बालों से नमी छीन लेती हैं और इसे रुखा और बेजान बना देती हैं। इस स्थिति में जिस तरह त्वचा पर सनस्क्रीन अप्लाई करने की सलाह दी जाती है, ठीक उसी तरह बालों के लिए भी एसपीएफ प्रोटेक्शन शैम्पू उपलब्ध है, जिसे आप बालों पर अप्लाई कर सकती हैं। लेकिन यूवी प्रोटेक्शन शैंपू जहरीले रसायनों से भरे होते हैं। इस स्थिति में अपने चेहरे या हाथों पर सनस्क्रीन लगाने के बाद हाथों को धीरे से अपने बालों के ऊपरी लेयर पर मिला लें।

क्या सच में चीनी से बेहतर है गुड़? जानिए पूरी सच्चाई

चाय से लेकर मिठाई तक में सबसे ज्यादा चीनी और गुड़ का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हर बार सवाल उठता है कि चीनी या गुड़ में से कौन सबसे अधिक हेल्दी है। गुड़ और चीनी दोनों को ही गन्ने के रस से बनाया जाता है, लेकिन दोनों को तैयार करने के तरीके में अंतर होने की वजह से ही इनके पोषक तत्व भी अलग-अलग होते हैं। अगर आप भी मीठा खाते समय हेल्दी विकल्प चुनना चाहते हैं, तो दोनों के फायदे और नुकसान जान लीजिए।

क्या कहते हैं एक्सपर्ट

गुड़ हो या चीनी दोनों का शरीर पर लगभग एक समान असर पड़ता है। चीनी या गुड़ जब हमारे शरीर में जाता है, तो वहां ग्लूकोज का निर्माण करता है। हमारा पैंक्रियाज चीनी और गुड़ में कोई फर्क नहीं करता है।

ग्लाइसेमिक इंडेक्स

- चीनी में 100% शुक्रोज है, जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 65 होता है।
- गुड़ में 65-85% शुक्रोज होता है और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 84 है।

मतलब गुड़ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स चीनी से ज्यादा होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स वह पैमाना है, जो बताता है कि भोजन में कितनी तेजी से शुगर बढ़ाता है। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली चीजें खाने से अक्सर मना किया जाता है।

गुड़ में कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं

डॉक्टर के अनुसार, जब गुड़

की बात होती है तो अकसर कहा जाता है कि इसमें आयरन, पोटैशियम, कैल्शियम और मिनरल्स होते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि इसकी मात्रा असल में बहुत कम होती है? तकरीबन 100 ग्राम गुड़ में 11 मिलीग्राम आयरन पाया जाता है। हालांकि सह सुनने में ठीक लग रहा है, लेकिन क्या हम 100 ग्राम गुड़ रोजाना खाते हैं। ज्यादातर लोग खाने के बाद एक छोटा टुकड़ा गुड़ का खाते हैं, जिससे 1.1 मिलीग्राम के करीब आयरन मिलता है। इतने से आय़रन को एक पालक के पत्तों से भी पाया जा सकता है। लेकिन, जब आप गुड़ का सेवन करते हैं, तो आयरन के साथ-साथ हमारे शरीर में शुगर और कैलोरी भी जाती है। उदाहरण के तौर पर, आयरन के लिए गुड़ खाना विटामिन-सी के लिए शराब में नींबू निचोड़ कर पीने के बराबर है। गुड़ हेल्दी है तो हम बिना किसी चिंता के इसका ज्यादा सेवन शुरू कर देते हैं। 2017 में प्रकाशित एक अध्ययन से पता चलता है कि अगर किसी पैकेट पर नेचुरल लिख दिया जाए तो लोग उसे 35% अधिक कंज्यूम करते हैं। डॉक्टरों के अनुसार, चीनी और गुड़ असल में दोनों एक ही तरह की चीजें हैं। दोनों ही फैटी लिवर, इंसुलिन रेजिस्टेंस और बेली फैट का कारण बन सकते हैं। चीनी और गुड़ में चयन से ज्यादा जरूरी है कि आप इसकी मात्रा पर ध्यान दें। एक चम्मच चीनी, दो चम्मच गुड़ से कहीं बेहतर है। हालांकि चीनी से शरीर में त्वरित एनर्जी मिलती है, लेकिन इससे ब्लड शुगर तेजी से बढ़ता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 100 ग्राम गुड़ में 98 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है और चीनी में 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मिलता है। दोनों में सिर्फ 2 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का ही अंतर है।

महिलाओं में एनीमिया क्यों बढ़ रहा है? जानें लक्षण और बचाव

खराब लाइफस्टाइल के कारण कई बीमारियों का खतरा बढ़ता जा रहा है। बच्चे हों या बुजुर्ग, महिलाएं हों या पुरुष हर किसी को लाइफस्टाइल से संबंधी समस्याएं हो रही हैं। महिलाओं के सेहत की बात करें, तो महिलाएं सबसे ज्यादा एनीमिया की शिकार हैं। ये तब होता है जब आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होती है। इसके कारण थकान, कमजोरी और चक्कर आने जैसे लक्षण होते हैं। इसके साथ ही कई परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है।

महिलाओं में एनीमिया की समस्या बहुत आम है, लेकिन कई बार वे इसके शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज कर देती हैं। एनीमिया का सबसे प्रमुख कारण महिलाओं द्वारा पोषण से भरपूर खाना न खाना भी है। एनीमिया तब होता है जब शरीर में आयरन की कमी हो जाती है, जिससे खून में हीमोग्लोबिन का स्तर गिर जाता है।

एनीमिया के लक्षण

इसके कारण कमजोरी, थकान, सिर दर्द, चक्कर आना, हाथ-पैर ठंडे रहना, सांस फूलना और चेहरे व होंठों का पीला पड़ना जैसे लक्षण दिख सकते हैं। कुछ महिलाओं को बाल झड़ने और नाखून कमजोर होने की भी समस्या हो सकती है। अगर समय रहते इस पर ध्यान न दिया जाए, तो यह गंभीर रूप ले सकता है और दिल से जुड़ी समस्याएं भी पैदा कर सकता है।

एनीमिया से बचने के उपाय

इससे बचने के लिए आयरन और फोलिक एसिड से भरपूर आहार लेना जरूरी है, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां, चुकंदर, अनार, सेब, गुड़, दालें और सूखे मेवे। साथ ही, विटामिन सी वाले फलों जैसे संतरा, आंवला

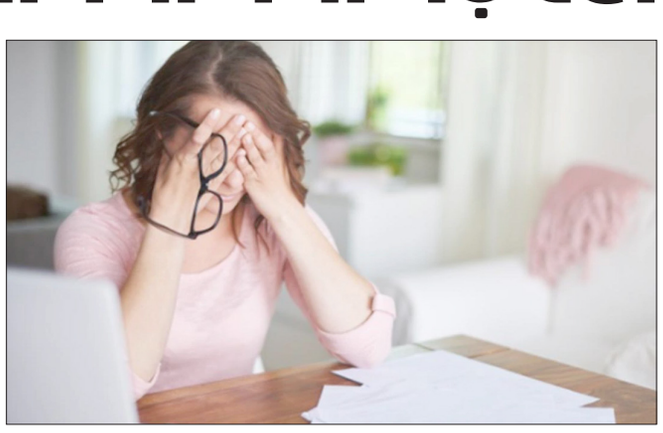

और नींबू का सेवन करना चाहिए। विटामिन सी शरीर में आयरन के अवशोषण में मदद करता है। अगर लगातार कमजोरी और थकान बनी रहे, तो डॉक्टर से खून की जांच करवानी चाहिए और सही इलाज लेना चाहिए।

एनीमिया के प्रकार फोलेट की कमी के कारण होने वाला एनीमिया

जब शरीर को रेड ब्लड सेल के निर्माण के लिए पर्याप्त फोलेट नहीं मिलता है, तब मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का कारण बनता है, जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं अपने सामान्य आकार से बड़ी हो जाती हैं।

आयरन की कमी

भारत में आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया सबसे अधिक होता है। इसमें शरीर में पर्याप्त आयरन नहीं बनता और आयरन की कमी बढ़ती जाती है, जिससे शरीर में हीमोग्लोबिन का स्तर घटता जाता है।

क्रोनिक रोग एनीमिया

यदि किसी व्यक्ति को लंबे समय से कोई इंफेक्शन है, तो उसे क्रोनिक एनीमिया हो सकता है। इसमें लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन कम हो जाता है।

गर्भावस्था के कारण एनीमिया

ये तब होता है जब महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान बच्चे के लिए ज्यादा रक्त की जरूरत होती है और महिलाएं उतनी मात्रा में संतुलित आहार का सेवन नहीं कर पाती है।

विटामिन बी12 की कमी के कारण होने वाला एनीमिया

लाल रक्त कोशिका के लिए आवश्यक विटामिन बी12 की कमी से के कारण फोलेट की कमी से समान मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है।

कैसे करें एनीमिया से बचाव

कॉफी-चाय का सेवन कम करें

अगर आप या आपका कोई जानने वाला एनीमिया से जूझ रहा है तो उसे चाय-कॉफी से दूर रहने की सलाह दें। दरअसल, चाय-कॉफी में मौजूद टैनिन शरीर में आयरन का अवशोषण कम कर देते हैं, जिसके चलते आयरन की कमी होने लगती है और एनीमिया का खतरा बढ़ जाता है।

डाइट का रखें विशेष ध्यान

एनीमिया के मरीजों को अपनी डाइट का विशेष ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर द्वारा बताए गए खाद्य पदार्थों को अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। इसके अलावा अपनी डाइट में विटामिन बी 12, विटामिन ए, आयरन और फोलेट रीच फूड को खाने में शामिल करना चाहिए। साथ ही मसालेदार और खट्टे भोजन से दूर रहना चाहिए।

फलों को करें डाइट में शामिल

एनीमिया के मरीजों को अपनी डाइट में कुछ ऐसे फल जरूर शामिल करने चाहिए, जो आयरन का बढ़िया स्त्रोत हों। ऐसे मरीजों को अपनी डाइट में संतरा, अंगूर, अनार, कीवी और सेब जैसे खट्टे फल शामिल करना चाहिए।

शराब का सेवन बंद करें

अगर आप एनीमिया से जूझ रहे हैं तो शराब और धूम्रपान से दूर रहें। इसका सीधा असर रेड ब्लड सेल्स पर पड़ता है। यह शरीर में अच्छे पोषक तत्वों का एब्जॉर्बशन रोक देता है।

हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन

एनीमिया से ग्रसित मरीजों को अपनी डाइट में हरी सब्जियां जरूर लेनी चाहिए। हरी सब्जियां आयरन और फोलेट का रिच सोर्स होती हैं, जो हीमोग्लोबिन और आरबीसी के निर्माण में मददगार होती हैं।

जंतर-मंतर पर उत्तराखंड पुलिस के कर्मचारी ने नौकरी छोड़ने की घोषणा की

भर्ती प्रक्रिया और पुलिस कार्रवाई पर उठाए सवाल

संवाददाता

नई दिल्ली। दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे प्रदर्शन के दौरान शुक्रवार को उत्तराखंड पुलिस के एक कर्मचारी शेर सिंह ने सार्वजनिक रूप से पुलिस सेवा छोड़ने की घोषणा की। उन्होंने पुलिस भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और पुलिस व्यवस्था को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि कई अन्य पुलिसकर्मी भी नौकरी छोड़ने पर विचार कर रहे हैं। हालांकि, उत्तराखंड पुलिस की ओर से बाद में यह कहा गया कि संबंधित कर्मचारी पहले से निलंबित था और उस पर विभागीय कार्रवाई चल रही है। मीडिया से बातचीत में शेर सिंह ने कहा कि 20 मार्च को हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई से आहत होकर उन्होंने यह फैसला लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदर्शन

के दौरान महिलाओं पर लाठीचार्ज किया गया, जिससे वे मानसिक रूप से व्यथित हुए और पुलिस सेवा छोड़ने का निर्णय लिया। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। शेर सिंह ने पुलिस भर्ती प्रक्रिया पर भी सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि भर्ती परीक्षाओं के प्रश्नपत्र खुलेआम बेचे जा रहे थे। हालांकि, इन आरोपों की किसी स्वतंत्र एजेंसी या सरकारी स्तर पर पुष्टि नहीं हुई है। उन्होंने यह भी आशंका जताई कि उत्तराखंड लौटने पर उन्हें हिरासत में लिया जा सकता है और उनकी आवाज दबाने का प्रयास किया जा सकता है।सभा को संबोधित करते हुए शेर सिंह ने कहा कि अब वह राजनीतिक नेताओं की सुरक्षा के बजाय आम लोगों के लिए काम करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि यदि न्याय की मांग करना बगावत माना जाता है तो वह स्वयं को बागी कहलाने के लिए तैयार हैं। इसके बाद उन्होंने मंच पर अपनी वर्दी से उत्तराखंड पुलिस का बैज हटाकर सीजेपी (Cockroach Janta Party) के संस्थापक अभिजीत दिपके को सौंप दिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी सामने आया है। शेर सिंह ने दावा किया कि वर्तमान परिस्थितियों से असंतुष्ट कई अन्य पुलिसकर्मी भी भविष्य में इस्तीफा दे सकते हैं। वहीं, उत्तराखंड पुलिस ने उनके आरोपों पर विस्तृत प्रतिक्रिया जारी नहीं की है। हालांकि, कुमाऊं रेंज के आईजी ने स्पष्ट किया कि शेर सिंह पहले से निलंबित थे और उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई लंबित है।

डॉ. वीरेन्द्र स्वरूप संस्थान में चंद्रशेखर आजाद जयंती पर श्रद्धांजलि सभा एवं विचार गोष्ठी आयोजित

संवाददाता

उन्नाव, उत्तर प्रदेश। लखनऊ-कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित डॉ. वीरेन्द्र स्वरूप मेमोरियल ट्रस्ट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन्स में अमर शहीद एवं महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर श्रद्धांजलि सभा एवं विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्वतंत्रता संग्राम में चंद्रशेखर आजाद के योगदान को याद करते हुए उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ नगर पालिका परिषद उन्नाव के अध्यक्ष प्रतिनिधि एवं समाजसेवी प्रवीण मिश्रा 'भानू', संस्थान के सचिव डॉ. अलक्षेन्द्र स्वरूप, रजिस्ट्रार डॉ. देशराज साहू, डायरेक्टर (इंजीनियरिंग) डॉ. अजय गौड़ तथा डायरेक्टर (मैनेजमेंट) डॉ. आशुतोष मिश्रा ने चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित कर किया। इस अवसर पर शिक्षकों एवं छात्र-छात्राओं ने चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली तथा चंद्रशेखर आजाद स्मृति पार्क पहुंचकर भी श्रद्धासुमन अर्पित किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रवीण मिश्रा 'भानू' ने कहा कि ऐसे आयोजन नई पीढ़ी में राष्ट्रभक्ति, देशप्रेम और स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान की भावना विकसित करने का महत्वपूर्ण

माध्यम हैं। रजिस्ट्रार डॉ. देशराज साहू ने कहा कि चंद्रशेखर आजाद का जीवन साहस, त्याग, आत्मसम्मान और राष्ट्रभक्ति का अनुपम उदाहरण है। उन्होंने विद्यार्थियों से उनके आदर्शों को अपनाकर राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आजाद का संघर्ष अन्याय के विरुद्ध डटकर खड़े होने की प्रेरणा देता है।डायरेक्टर (इंजीनियरिंग) डॉ. अजय गौड़ ने चंद्रशेखर आजाद के जीवन संघर्ष, अदम्य साहस और स्वतंत्रता आंदोलन में उनके अतुलनीय योगदान पर प्रकाश डाला तथा देशभक्ति से ओत-प्रोत रचनाओं के माध्यम से उनके व्यक्तित्व को याद किया। डायरेक्टर (मैनेजमेंट) डॉ. आशुतोष मिश्रा ने विद्यार्थियों को राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए ईमानदारी, अनुशासन और सामाजिक उत्तरदायित्व के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने का संकल्प दिलाया। कार्यक्रम के अंत में शिक्षिका डॉ. अंकिता यादव ने सभी अतिथियों, वक्ताओं और सहयोगियों के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर डॉ. आशीष तिवारी, डॉ. दीपक सिंह, डॉ. अंकित कटियार, दीपक सोनकर, शिखा शर्मा, कीर्ति भट्ट, ब्रजेन्द्र शुक्ला, डॉ. अखिलेन्द्र सिंह, मीनाक्षी दीक्षित, दीपाली निषाद, सोनिया राय, तनवीर जहाँ, नूपुर पाल, अक्षिता मिश्रा, विनय मिश्रा, नेहा शुक्ला, मोहम्मद कलाम सहित संस्थान के प्राध्यापकगण एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

अपर जिलाधिकारी ने राजस्व वसूली में तेजी लाने के दिए निर्देश, गरीबों को त्वरित न्याय दिलाने पर जोर

देवेश प्रताप सिंह राठौर

झांसी, उत्तर प्रदेश। कलेक्ट्रेट के नवीन सभागार में आयोजित कर-करेत्तर एवं प्रवर्तन कार्यों की समीक्षा बैठक में अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) शिव प्रताप शुक्ल ने राजस्व वसूली में तेजी लाने, लंबित राजस्व वादों के शीघ्र निस्तारण तथा गरीबों को त्वरित न्याय उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी विभाग कार्ययोजना बनाकर शासन द्वारा निर्धारित वसूली लक्ष्य को हर हाल में पूरा करें। बैठक में अपर जिलाधिकारी ने उपजिलाधिकारियों एवं तहसीलदारों को निर्देश दिए कि धारा-24, धारा-34 एवं धारा-67 के अंतर्गत लंबित वादों को सूचीबद्ध कर विशेष अभियान चलाते हुए उनका शीघ्र निस्तारण कराया जाए। उन्होंने पुराने लंबित मामलों को प्राथमिकता देने पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि "न्याय पहुंचे गरीब के द्वार" की भावना के अनुरूप कार्य करते हुए गरीबों को समयबद्ध न्याय दिलाना प्रशासन की प्राथमिकता है। सरकारी भूमि अथवा गरीबों की जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले भू-माफियाओं की पहचान कर उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही ऐसे मामलों में मौके पर जांच कर पीड़ितों को शीघ्र न्याय दिलाया जाए। बैठक में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) पल्लवी मिश्रा ने कर-करेत्तर वसूली की समीक्षा करते हुए कहा कि कई विभागों की प्रगति शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप संतोषजनक नहीं है। उन्होंने सभी विभागों को प्रभावी रणनीति बनाकर प्रवर्तन कार्यों में तेजी लाने और शत-

प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने के निर्देश दिए। उन्होंने समस्त उपजिलाधिकारियों एवं तहसीलदारों को जिले के शीर्ष दस बकायेदारों पर विशेष कार्रवाई करने के निर्देश दिए। एसडीएम सदर, मोंठ और टहरौली को संबंधित बकायेदारों से शीघ्र शत-प्रतिशत वसूली सुनिश्चित करने को कहा गया। समीक्षा के दौरान वाणिज्य कर विभाग की प्रगति पर नाराजगी जताते हुए अपर जिलाधिकारी ने बताया कि विभाग ने 153.54 करोड़ रुपये के मासिक लक्ष्य के सापेक्ष 88.33 करोड़ रुपये की ही वसूली की है। उन्होंने अधिकारियों से वसूली के स्रोतों की जानकारी लेते हुए लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रभावी कार्ययोजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। राज्य उत्पाद शुल्क (आबकारी) विभाग की समीक्षा करते हुए दुकानों की नियमित जांच बढ़ाने, प्रवर्तन कार्रवाई तेज करने तथा शादी एवं अन्य आयोजनों के लिए एक दिवसीय लाइसेंस जारी कर राजस्व बढ़ाने के सुझाव दिए गए। वहीं मालकर, वाहन कर और यात्री कर की समीक्षा में विभाग की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया गया। विभाग ने 14.43 करोड़ रुपये के लक्ष्य के सापेक्ष 13.65 करोड़ रुपये की वसूली की है। अधिकारियों को नए वाहनों की बिक्री पर नजर रखते हुए वसूली बढ़ाने के निर्देश दिए गए। बैठक के अंत में अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) शिव प्रताप शुक्ल ने न्यायिक मजिस्ट्रेटों से अधिक से अधिक वादों के निस्तारण का प्रयास करने को कहा। उन्होंने विशेष रूप से धारा-34, धारा-80, धारा-116 तथा धारा-24 से संबंधित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि आमजन, विशेषकर गरीबों को बार-बार न्यायालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। बैठक में विभागीय कार्रवाई, ऑनलाइन खसरा फीडिंग, आपदा राहत, संपूर्ण समाधान दिवस, भू-आवंटन, ऑडिट आपत्तियों के निस्तारण, चकबंदी तथा आबकारी, परिवहन, खनन, वन, सिंचाई, विद्युत और वाणिज्य कर विभागों की राजस्व वसूली प्रगति की भी विस्तृत समीक्षा की गई। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी (न्याय) अरुण कुमार गौड़, अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे) योगेंद्र कुमार, नगर मजिस्ट्रेट प्रमोद झा, खान अधिकारी शैलेन्द्र सिंह सहित सभी उपजिलाधिकारी, तहसीलदार एवं विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

उन्नाव में भारतीय सर्व धर्म संसद के धर्मगुरुओं का भव्य स्वागत, सामाजिक सद्भाव और संवाद पर दिया जोर

संवाददाता

उन्नाव, उत्तर प्रदेश। भारतीय सर्व धर्म संसद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील जी महाराज, जगद्गुरु रामानंदाचार्य स्वामी सतीशाचार्य जी महाराज सहित विभिन्न धर्मों के धर्मगुरुओं का उन्नाव आगमन पर होटल शिवा इन में भव्य स्वागत किया गया। सभी धर्मगुरु लखनऊ में आयोजित एक विद्यालय के कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। स्वागत समारोह का आयोजन भारतीय सर्व धर्म संसद के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र वर्मा बाबा के नेतृत्व में किया गया। इस अवसर पर इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी के सभापति अमित मिश्रा, युवा नेता सौरभ वर्मा, लक्ष्य निगम, कुंवर प्रीत सिंह, मनोज कुमार, सचिन वर्मा, अनुप, दिनेश सहित विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भारतीय सर्व धर्म संसद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील जी महाराज ने कहा कि उन्नाव आपसी भाईचारे और सामाजिक सौहार्द की मिसाल है, जहां सभी धर्मों के लोग मिल-जुलकर

दूसरे के धार्मिक स्थलों पर जाते हैं और धार्मिक सौहार्द बनाए रखना समाज के हित में है। उन्होंने धार्मिक मुद्दों पर अनावश्यक विवाद और बयानबाजी से बचने की आवश्यकता पर बल दिया। मौलाना मुहम्मद अजाजुर रहमान ने कहा कि यदि युवा अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं तो सरकार और युवाओं के बीच संवाद होना चाहिए, ताकि समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से निकाला जा सके। रेव. फादर सेवारिटयन कांलिठाणाम ने बताया कि लखनऊ के एक विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में सभी धर्मों और समुदायों के बच्चे भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय सर्व धर्म संसद समाज के प्रत्येक वर्ग और देश के युवाओं के हित में कार्य कर रही है। इस अवसर पर भिक्खू संघेसिना, परमजीत सिंह चंडोक सहित भारतीय सर्व धर्म संसद के अनेक पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान सभी धर्मों के बीच आपसी भाईचारे, शांति और सामाजिक सद्भाव का संदेश दिया गया।

नवादा में आकाशीय बिजली गिरने से चार लोगों की मौत, दो महिलाएं झुलसीं

संवाददाता

नवादा। बिहार के नवादा जिले के नारदीगंज प्रखंड अंतर्गत सांगोवर गांव में शुक्रवार को आकाशीय बिजली गिरने से चार लोगों की मौत हो गई, जबकि दो महिलाएं गंभीर रूप से झुलस गईं। घायलों का इलाज नारदीगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) में चल रहा है। इस दर्दनाक हादसे के बाद पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। प्राप्त जानकारी के

अनुसार मृतकों में तीन किसान और एक 12 वर्षीय बालक शामिल हैं। सभी लोग खेत में कृषि कार्य कर रहे थे। दोपहर बाद अचानक मौसम का मिजाज बदला और तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए खेत में काम कर रहे लोग पास के एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। इसी दौरान तेज गर्जना के साथ आकाशीय बिजली गिरी, जिसकी चपेट में आने से छह लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और सभी घायलों को तत्काल नारदीगंज पीएचसी पहुंचाया। चार लोगों को मृत घोषित कर दिया, जबकि दो महिलाओं को प्राथमिक उपचार के बाद निगरानी में रखा गया है।

हैदराबाद एयरपोर्ट पर नकली टिकटों के साथ दो नेपाली नागरिक गिरफ्तार

संवाददाता

हैदराबाद। हैदराबाद के राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (आरजीआईए) पर शुक्रवार को इमीग्रेशन और एयरलाइंस अधिकारियों ने दुबई जाने की तैयारी कर रहे दो नेपाली नागरिकों को फर्जी हवाई टिकट के साथ हिरासत में लिया। प्रारंभिक जांच में दोनों के टिकट नकली पाए गए, जिसके बाद उन्हें शमशाबाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। अधिकारियों के अनुसार दोनों नेपाली नागरिक दुबई जाने वाली उड़ान से यात्रा करने के लिए राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचे थे। बोर्डिंग प्रक्रिया से पहले एयरलाइंस और इमीग्रेशन अधिकारियों ने उनके यात्रा दस्तावेजों और टिकटों की नियमित जांच की। इसी दौरान टिकटों में कुछ संदिग्ध विसंगतियां दिखाई देने पर उनकी गहन जांच की गई। जांच

में दोनों यात्रियों के हवाई टिकट फर्जी पाए गए। इसके बाद अधिकारियों ने तत्काल दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की और आगे की कार्रवाई के लिए शमशाबाद पुलिस को सौंप दिया। पुलिस और संबंधित एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि दोनों यात्रियों को नकली टिकट किसने उपलब्ध कराए। जांच एजेंसियों को आशंका है कि इस मामले के पीछे किसी ट्रैवल एजेंट या फर्जी टिकट तैयार करने वाले संगठित गिरोह का हाथ हो सकता है। इस पहलू को ध्यान में रखते हुए मामले की विभिन्न कोणों से जांच की जा रही है।

बिजली बिल नहीं चुकाने पर 10 हजार सरकारी कनेक्शन काटे गए

■ अबतक 51 करोड़ रुपये का बिजली बिल बकाया

संवाददाता

धारायपुर। छत्तीसगढ़ में सरकारी विभागों के बढ़ते बिजली बिल बकाये को देखते हुए बिजली कंपनी ने सख्त कदम उठाते हुए 10 हजार से अधिक सरकारी बिजली कनेक्शनों को स्थायी रूप से काट दिए हैं। इसके अलावा, 1 अगस्त से सभी सरकारी कार्यालयों में प्री-पेड बिजली व्यवस्था लागू करने की तैयारी पूरी कर ली गई है।

इन कनेक्शनों पर करीब 51 करोड़ रुपये का बिजली बिल बकाया था। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी ने अपने वित्तीय प्रबंधन और बढ़ते घाटे को देखते हुए इन 10,000 सरकारी बिजली कनेक्शनों को काटने की सूची और आंकड़े जारी किए हैं। उल्लेखनीय है कि हाल में ही संपन्न हुए विधानसभा के मानसून सत्र में खुद राज्य सरकार ने

माना था कि विभिन्न विभागों पर 3,117 करोड़ रुपये से अधिक का बकाया है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी द्वारा आज दी गई जानकारी के अनुसार, प्रदेश के 40 सरकारी विभागों पर कुल 3,432 करोड़ रुपये से अधिक की देनदारी होने से बिजली कंपनियों के वित्तीय प्रबंधन पर लगातार दबाव बना हुआ है।अधिकारियों ने बताया है कि भुगतान के लिए संबंधित विभागों को कई बार नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन समय पर राशि जमा नहीं होने के कारण स्थायी रूप से कनेक्शन काट दिए गए । जिन सरकारी कनेक्शनों का भविष्य में दोबारा उपयोग किया जाएगा, उन्हें पुनः चालू कराने से पहले पूरा बकाया जमा करना अनिवार्य होगा। वहीं जिन परिसरों में बिजली आपूर्ति अभी भी जारी है, वहां ड्यूज रिकवरी एक्ट के तहत बकाया राशि को किस्तों अथवा नियमित बिजली बिलों में समायोजित कर वसूला जाएगा। यह कार्रवाई अंबिकापुर, दुर्ग, बिलासपुर, रायपुर, जगदलपुर, महासमुंद, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर और राजनांदगांव सहित अन्य सर्कलों में बड़ी संख्या में की गई है । रायपुर के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी व्यापक स्तर पर बड़े स्टार पर कनेक्शन काटे गए हैं। उल्लेखनीय है कि हाल ही में संपन्न हुए मानसून सत्र में छत्तीसगढ़ विधानसभा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा प्रस्तुत आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, कुल 3,117.49 करोड़ रुपये के सरकारी बकाये में से लगभग 85 प्रतिशत हिस्सा सिर्फ दो प्रमुख विभागों का है। सर्वाधिक बकाया वाले शीर्ष विभाग नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग है। इस विभाग पर सबसे बड़ा 1,525.18 करोड़ रुपये का बकाया है। इसमें निकायों के वॉटर फिल्टर प्लांट, स्ट्रीट लाइट और कार्यालयों के बिल शामिल हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग पर 1,057.56 करोड़ रुपये की भारी राशि लंबित है। ग्रामीण क्षेत्रों की नल-जल योजनाएं और स्ट्रीट लाइट इसका मुख्य कारण हैं। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग पर करीब 111 करोड़ रुपये का बिजली बिल बकाया है। जबकि गृह विभाग, स्वास्थ्य, स्कूल शिक्षा, और सिंचाई जैसे अन्य सभी विभागों को मिलाकर कुल 1,758 करोड़ रुपये से अधिक की देनदारी है। आवश्यक सेवाओं को लेकर सरकार की नीतिबिजली कंपनी ने साफ किया है कि आम जनता से जुड़ी आवश्यक सेवाओं (जैसे पेयजल आपूर्ति/नल-जल, सरकारी अस्पताल, स्ट्रीट लाइट और स्कूल) के कनेक्शन सीधे नहीं काटे जाते हैं। इसी कार्रवाई के हिस्से के रूप में अगले महीने 1 अगस्त 2026 से सभी सरकारी दफ्तरों में प्रीपेड मीटर अनिवार्य किए जा रहे हैं।

मालिक, प्रकाशक व मुद्रक- सुनील कुमार तिवारी द्वारा सोमानी प्रिंटिंग प्रेस, यूनिट नं. ०४, ग्राउंड फ्लोर, एन. के. इंडस्ट्रीयल इस्टेट, ऑफ आरे रोड, नियर प्रवासी इंडस्ट्रीयल इस्टेट, गेट नं ०२, गोरेगांव (पूर्व) मुंबई-४०००६३ से मुद्रित व ६१७, बिल्डिंग नं. १४ नियर शिव शक्ति बिल्डिंग, गोलीबार रोड, सान्ताक्रूज (पूर्व), मुंबई-४०००५५ से प्रकाशित। **संपादक सुनील कुमार तिवारी,** RNI. NO. MAHMUL/2017/74054, **संपादकीय कार्यालय: कंटेश्वर सिंह चाल, अपोजीट एकताड़ मंडल, साईं बाबा रोड, खार (पूर्व), मुंबई- 400051, Mob. 8898271111**